आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

जसजीत सिंह बेदी से पहले जे.

रश्मीत कौर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2022 का सीआरडब्ल्यूपी No.3251

13 जून, 2022

क) भारत का संविधान, 1950 Art. 226 -हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956-धारा 6-बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेखन-पिता और दादा-दादी को नाबालिग लड़की पैदा करने का निर्देश और नाबालिग बच्ची को माँ और बच्चे के स्वाभाविक अभिभावक के पास रखने का निर्देश-आयोजित, माँ के प्यार और देखभाल के स्थान पर माँ जैसी कोई संपत्ति या माँ नहीं हो सकती है, इसलिए, बच्ची के स्वस्थ विकास के लिए मातृ देखभाल और स्नेह अनिवार्य है-भले ही पिता के कथन को सच माना जाए कि बच्चा माँ के साथ जाने से इनकार कर देता है, लेकिन अपने आप में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र का बच्चा नहीं जानता कि उसके सर्वोत्तम हित में क्या है-लंबे समय तक बच्ची के लाभ और कल्याण के लिए, किसी भी कल्पना से नहीं कहा जा सकता बच्चों का कल्याण अच्छे तरीके से दादा–दादी या माता के द्वारा किया जा सकता है।

माना जाता है कि लड़की, अर्थात् अवनीत तुर्का का जन्म 01.08.2017 को हुआ था और इसलिए वह पाँच साल से कम उम्र की है। प्रतिवादी नं.7 और 8 द्वारा उसे भारत वापस लाया गया। 23.1.2020 पर 7 और 8 जिसके बाद कोविड-19 के कारण याचिकाकर्ता-माँ मार्च 2022 तक उसे देखने में असमर्थ थी।इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब बच्ची ने याचिकाकर्ता का साथ छोड़ दिया तो वह लगभग ढाई साल की थी और उसने अपने बढ़ते हुए साल अपने दादा-दादी यानी प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के साथ बिताए।पिता के अनुसार, बच्ची ने उस समय याचिकाकर्ता के साथ जाने से इनकार कर

दिया था जब याचिकाकर्ता 28.03.2022 पर अपने माता-पिता के घर के लिए रवाना हुई थी।मैं यहां यह इंगित कर सकता हूं कि भले ही पिता के बयान को सच्चाई के रूप में लिया जाए कि बच्ची ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अपने आप में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र का बच्चा नहीं जानता कि उसके सर्वोत्तम हित में क्या है।यह दोहराया जा सकता है कि बच्चा जनवरी 2020 से मार्च 2022 के बीच दो वर्षों में अपनी माँ से नहीं मिला था।जाहिरा तौर पर, अपने नियंत्रण से परे कारणों से याचिकाकर्ता भारत वापस आने में असमर्थ थी।

प्रतिवादी संख्या के साथ एक बंधन 7 & 8 जिनके साथ वह पिछले दो साल से अधिक समय से रह रही है, जिसके कारण उसने कहा होगा कि वह अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती है। हालांकि, लंबे समय में बच्ची के लाभ और कल्याण के लिए, किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची के कल्याण का बेहतर ध्यान दादा-दादी यानी मां द्वारा रखा जाएगा।अन्यथा भी, 05 वर्ष से कम आयु के बच्ची के मामले में (जो यहाँ मामला है) अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होनी चाहिए।वास्तव में प्रतिवादी संख्या द्वारा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है **कि बच्चे की देखभाल मां के पास** क्यों नहीं होनी चाहिए।

(पैरा 18)

ख) भारत का संविधान, 1950 Art. 226 -हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956-धारा 6-नाबालिग की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट-रखरखाव-आयोजित, जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में दीवानी न्यायालयों का सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निश्चित रूप से बनाए रखने योग्य है, विशेष रूप से, जहां यह दिखाया गया है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्ची **को हिरासत में रखना अवैध था, बिना किसी कानून के अधिकार के और** बच्ची **के नुकसान के लिए भी था।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि विभिन्न निर्णयों (उपर्युक्त) के साथ हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम , 1956 की खंड 6 के अवलोकन से पता चलेगा कि बाल

अभिरक्षा मामलों में सामान्य उपाय हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम , 1956 और संरक्षकता और वार्ड अधिनियम , 1890 के तहत निहित है।दीवानी अदालतों द्वारा की जाने वाली जांच और एक रिट कोर्ट द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो संक्षिप्त प्रकृति का है जहां हलफनामों के आधार पर अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।इसलिए , जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है , वहां अदालत एक रिट कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पक्षों को दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दे सकती है।इसलिए , यह केवल असाधारण मामलों में है, जहां नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका में असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया जाएगा।इस प्रकार, जहां किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में सिविल न्यायालयों का सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है , वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट निश्चित रूप से बनाए रखने योग्य है , इसलिए, जहां यह दिखाया गया है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्ची को हिरासत में रखना अवैध था, बिना किसी कानून के अधिकार के और बच्ची के नुकसान के लिए भी था।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने कहा,

परवीन कुमार अग्रवाल , उप महाधिवक्ता हरियाणा।प्रतिवादी सं . की ओर से अधिवक्ता कंवलजीत सिंह **प्रतिवादी संख्या** 7 & 8 **के लिए**

जस्जीत सिंह बेदी, जे।

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान आपराधिक रिट याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए दायर की गई है , जिसमें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की नाबालिग बच्ची यानी **जोकि श्री अविकास तुर्का** की बेटी अवनीत तुर्का (आयु 4-1/2 वर्ष) को पेश करने का निर्देश दिया गया है। अंबाला छावनी के **मकान न. 174** सेक्टर डी, डिफेंस कॉलोनी के निवासी अविकास तुर्का

नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंप देते हैं , जो बच्ची की मां और प्राकृतिक अभिभावक है।

(2) याचिका से सामने आने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जिसका जन्म शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में हुआ था , उसका विवाह प्रतिवादी नं .7 & 8, शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में 174-D, सेक्टर डी, डिफेंस कॉलोनी, अंबाला छावनी के साथ दिनांक 15.12.2013 गंभीर फार्म हुआ शाहबाद जिला कुरूक्षेत्र में हुई थी। शादी के तुरंत बाद याचिकाकर्ता और विकास तुर्का ऑस्ट्रेलिया चले गए और शादी के तीन साल बाद एक बेटी यानी अवनीत तुर्का का जन्म मैटर अस्पताल , साउथ ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, दिनांक 01.08.2017 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ। नाबालिग बच्ची बच्ची के पासपोर्ट का विवरण सलंगन का विवरण पी-3 के रूप में संलग्न है।

इस बीच, याचिकाकर्ता ने ग्रिफ़िथ विश्वविद्यालय , ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया से नर्सिंग में स्नातक की डिग्री के साथ एक नर्स के रूप में अर्हता प्राप्त की और आरएसएल रिमेम्बरेंस विलेज, माउंट ऑस्टिन, न्यू साउथ वेल्स , ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 67,000/- का वार्षिक वेतन प्राप्त कर रहा है।

(3) हालाँकि समय -समय पर दंपति के बीच वैवाहिक कलह होती थी , हालाँकि, याचिकाकर्ता जो अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी , वह 29.04.2019 से 13.05.2019 के बीच अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत गई थी।उसके सास -ससुर यानी प्रतिवादी संख्या। 7 & 8 याचिकाकर्ता, उसके पति और उनके बच्ची अवनीत तुर्का से मिलने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी।

(4) याचिकाकर्ता के अनुसार, 23.01.2020 पर उसके ससुराल वाले नाबालिग बच्ची अवनीत तुर्का को अपने साथ भारत लाए और याचिकाकर्ता को इसके तुरंत बाद भारत आना था।हालाँकि, 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद विदेशी यात्रा प्रतिबंधों की अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन के कारण याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया में फंस गया और 2020 और 2021 में भारत नहीं आ सका।इसके बाद याचिकाकर्ता 21.03.2022 पर भारत आया।

411

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

परिवार और रिश्तेदार से मिलने 2 साल के अंतराल के बाद #174, सेक्टर डी, डिफेंस कॉलोनी, अंबाला छावनी में स्थित वैवाहिक घर गई। याचिकाकर्ता वहां लगभग एक सप्ताह रही और अपनी ससुरावालों प्रतिवादी नं. 7 व 8 के द्वारा घरेलू हिंसा और दुरव्यवहार का सामना किया। प्रतिवादीग नं. 7 व 8 उसी के कारण, याचिकाकर्ता ने जिला कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थित अपने माता -पिता के घर जाने का फैसला किया और अपने बैग पैक करने और अपनी बेटी अवनीत तुर्का को उसके माता -पिता के घर जाने के लिए तैयार करने के बाद , प्रतिवादी संख्या। 7 & 8 याचिकाकर्ता को अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी।

(5) उपरोक्त घटना और घरेलू हिंसा के कारण, याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन पंजोखरा से संपर्क किया , और प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के खिलाफ दिनांक 28.03.2022 (अनुलग्नक P-1) की शिकायत दर्ज की। 7 & 8 प्रतिवादी संख्या की जबरन हिरासत से अपनी नाबालिग बेटी की रिहाई की मांग करना। 7 और 8 और उसे अभिरक्षा सौंपना।30.03.2022 पर प्रतिवादी संख्या 7 और 8 अकेले पुलिस स्टेशन पंजोखरा में पुलिस के सामने पेश हुए और नाबालिग बच्ची को पेश नहीं किया। पुलिस ने फिर से प्रतिवादी संख्या 7 और 8 को बुलाया।7 और 8 और पी. एस. पंजोखरा में याचिकाकर्ता ने 6.4.2022 पर नाबालिग बच्ची बच्ची को पेश करने का निर्देश दिया। हालाँकि, जबकि प्रतिवादी की संख्या। 7 और 8 6.4.2022 पर उपस्थित हुए लेकिन उन्होंने नाबालिग बच्ची को पेश नहीं किया और किसी न किसी बहाने से मामले को लटका के रखा।

(6) इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से वैवाहिक घर का दौरा किया।हालाँकि , उक्त घर में ताला लगा हुआ था और पूछताछ करने पर पड़ोसी ने उसे सूचित किया कि प्रतिवादी नं- 7 और 8 घर छोड़ दिया था और उनके वर्तमान स्थान का पता नहीं था।इस प्रकार यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी का इरादा सं। 7 और 8 याचिकाकर्ता को

परेशान करना और उसे अपनी नाबालिग बेटी से दूर रखना था।उपरोक्त तथ्यों के कारण, वर्तमान याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई।

(7) यह मामला इस न्यायालय के समक्ष 08.04.2022 पर सुनवाई के लिए आया जब 5.5.2022 के लिए प्रस्ताव का नोटिस जारी किया गया था।उक्त तिथि पर , वकील प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के लिए उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 7 और 8 और इस न्यायालय ने पक्षकारों को इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया , जिसमें प्रतिवादी को आगे का निर्देश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 7 और 8 याचिकाकर्ता को Rs.25,000/- की राशि का भुगतान करना।इसके बाद मामले को 16.5.2022 तक स्थगित कर दिया गया।उस दिन प्रतिवादी संख्या द्वारा समय मांगा गया था। 7 और 8 और मामला 27.05.2022 तक स्थगित कर दिया गया।इस बीच मध्यस्थता कार्यवाही में याचिकाकर्ता को नकद में 1,000/- की राशि का भुगतान किया गया था , लेकिन एक सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सका और इसलिए, मामले को इस न्यायालय में वापस भेज दिया गया। 26.5.2022 पर प्रतिवादी संख्या के लिए वकील को नाबालिग बच्ची को अगली तारीख जोकि 27.05.2022 को अदालत में लाने के लिए कहा गया

लेकिन बच्ची को अदालत में नहीं लाया गया। (8) इस बीच, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6 की ओर से श्री राज सिंह, एच. पी. एस., डी. एस. पी., अंबाला के एक शपथ पत्र के माध्यम से दिनांकित 28.04.2022 का जवाब प्रस्तुत किया गया। उक्त जवाब के अनुसार 08.04.2022 पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपने ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती है और कुरुक्षेत्र में अलग से उचित शिकायत दर्ज कराएगी।उनके पति अविकास तुर्का का बयान उसी दिन दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा था कि वह और उनके माता -पिता बच्ची बच्ची को उनकी पत्नी को देने के लिए तैयार थे क्योंकि उनकी बेटी को दोनों माता -पिता की आवश्यकता थी और वे छह-छह महीने की अवधि के लिए हिरासत साझा कर सकते थे।ऐसा इसलिए था क्योंकि बच्ची की देखभाल उसके माता -पिता द्वारा की जा रही थी और अन्यथा वह

28.03.2022 पर याचिकाकर्ता के साथ नहीं जाना चाहते थे।हालाँकि , अगर बच्चा चाहेगा तो वे बच्ची बच्ची को माँ के साथ जाने देंगे।

(9) प्रतिवादी सं। 7 और 8 इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान कोई जवाब दाखिल नहीं किया।हालांकि, प्रतिवादी के लिए वकील संख्या। 7 और 8 उन्होंने कहा कि वे याचिकाकर्ता के साथ नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा साझा करने के लिए तैयार थे।यह पूछे जाने पर कि यह कैसे संभव होगा क्योंकि याचिकाकर्ता और उसके पति अविकास तुर्का ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और प्रतिवादी संख्या। 7 और 8 वे आम तौर पर अंबाला, हरियाणा, भारत के निवासी थे , उनके वकील द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी।

(10) मैंने पार्टियों के वकील विस्तार से सुना है।

(11) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि बच्ची को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 द्वारा भारत लाया गया था। 7 & 8 जनवरी 2020 में इस स्पष्ट समझ के साथ भारत आया कि याचिकाकर्ता मुकदमे का पालन करेगा और उसके बाद बच्ची को ऑस्ट्रेलिया वापस लाएगा जहां वह आम मुकदमा पर याचिकाकर्ता के साथ रह रही है।हालाँकि , कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वह मार्च 2022 तक देश वापस यात्रा करने में असमर्थ थीं। जब वह वापस आई और अपने बच्ची को अपने माता -पिता के घर ले जाने का प्रयास किया, तो प्रतिवादी संख्या 7 और 8 द्वारा इसका विरोध किया गया। बच्ची का यह गैरकानूनी , अवैध और जबरन प्रतिधारण याचिकाकर्ता को राहत का हकदार बनाता है जैसा कि इस याचिका में अनुरोध किया गया है , विशेष रूप से तब जब

लड़की की उम्र 05 वर्ष से कम हो और उसे याचिकाकर्ता -माँ की देखभाल, प्यार और ध्यान की आवश्यकता हो।वास्तव में नाबालिग बच्ची बच्ची की अभिरक्षा हमेशा याचिकाकर्ता के पास रही है , अतीत में कुछ अवसरों को छोड़कर जब बच्चा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के साथ रहता था। लेकिन प्रतिवादी संख्या 7 और 8 की ऐसी घटना। बच्ची के साथ भाग लेने से इनकार करना कभी नहीं हुआ था।वास्तव में बच्ची का कल्याण सर्वोपरि था और इसलिए अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंपी जानी चाहिए।हिंदू अल्पसंख्यक और रश्नीत कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य की खंड 6 का संदर्भ दिया गया है।

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

संरक्षकता अधिनियम, 1956 में यह तर्क दिया गया है कि 05 वर्ष से कम आयु की बालिका की अभिरक्षा आम तौर पर मां के पास होनी चाहिए।

(12) प्रतिवादी सं. 7 और 8 के लिए वकील। जांच एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान संलग्नक आर -1 के अनुसार, उसने केवल विकास तुर्का के बयान को दोहराया है।वह कुछ भी महत्वपूर्ण बात नहीं बता पाए हैं कि नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा प्रतिवादी संख्या 7 और 8 द्वारा क्यों समर्थ जानी चाहिए। सिवाय यह कहने के कि बच्चा दादा-दादी से जुड़ा हुआ है और वे याचिकाकर्ता के साथ अभिरक्षा साझा करने के लिए तैयार थे।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है , वह यह समझाने में असमर्थ रहा है कि बच्ची की अभिरक्षा को दादा-दादी यानी प्रतिवादी संख्या 7 and 8 के साथ कैसे साझा किया जा सकता है। जो भारत के निवासी हैं और याचिकाकर्ता, माँ जो ऑस्ट्रेलिया की निवासी थी।

(13) विद्वान राज्य वकील ने केवल राज्य जवाब के दिनांकित 28.04.2022 के संस्करण को दोहराया है।

(14) आगे बढ़ने से पहले हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम , 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार हैं:-

"6. एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक।—

हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक; नाबालिग के व्यक्ति के साथ -साथ नाबालिग की संपत्ति के संबंध में (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर), हैं -

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में-पिता और उसके बाद माँ:

बशर्ते कि पाँच वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होगी;

(ख) अवैध लड़के या अवैध अविवाहित लड़की के मामले में -माँ, और उसके बाद , पिता;

(ग) विवाहित लड़की के मामले में-पति:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा -(ए) यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या

(ख) यदि उसने एक संन्यासी (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी) बनकर पूरी तरह से और अंत में दुनिया का त्याग कर दिया है।

स्पष्टीकरण।—इस खंड में "पिता" और

"माँ में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं हैं।

13. नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए।—

(1) अदालत द्वारा किसी भी व्यक्ति को हिंदू नाबालिग के अभिभावक के रूप में घोषित करने में, नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा।

(2) इस अधिनियम के तहत हिंदुओं के बीच विवाह में संरक्षकता से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रावधानों के आधार पर संरक्षकता का हकदार नहीं होगा , यदि अदालत की राय है कि उसका संरक्षकता नाबालिग के कल्याण के लिए नहीं होगा।

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर जो मुददा हाथ में है और इस संबंध में कुछ प्रासंगिक निर्णय इस प्रकार हैं-

तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य में

मातृ चाची और चाचाओं के पास उस बच्ची की देखभाल थी जिसकी माँ बीमार थी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता ने बच्ची की अभिरक्षा मांगी तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिरक्षा प्रदान करते हुए,

"11. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की रखरखावः- द.

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि नाबालिग की अभिरक्षा के प्रश्न पर निर्णय लेने में , नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि है और अपीलार्थियों द्वारा नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा को अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है ताकि बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वीकार किया जा सके जो एक असाधारण उपाय है और उच्च न्यायालय ने नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा को पहले प्रतिवादी पिता को सौंपने का आदेश देने में गलती की -

डॉ. वीणा कपूर बनाम वरिंदर कुमार कपूर (1981) 3 एस. सी. सी. 92 और सरिता शर्मा बनाम सुशील शर्मा 2000 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 367:(2000) 3 एससीसी 14

और कुछ अन्य मामलों में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बच्चों के कल्याण के लिए एक पूर्ण और गहन जांच की आवश्यकता है और इसलिए , उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने के बजाय , प्रतिवादी को दीवानी अदालत में उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना चाहिए था।विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि हालांकि पिता एक स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते वरीयता

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा का अधिकार वरीयता के आधार पर पिता के पास है, बच्ची के कल्याण और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , अपीलकर्ताओं द्वारा बच्ची की अभिरक्षा को अवैध या अनुचित नहीं कहा जा सकता है ताकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके असाधारण उपाय का आह्वान करना उचित ठहराया जा सके।

12. इस तर्क का विरोध करते हुए , प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामले के दिए गए तथ्यों में , उच्च न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की असाधारण शक्ति है और उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने में सही था।विद्वान अधिवक्ता ने इस पर भरोसा रखा है

गौहर बेगम बनाम सुग्गी @नजमा बेगम और अन्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 93 और श्रीमती. मंजू मालिनी शेषाचलम डी/ओ श्री आर. शेषाचलम बनाम विजय थिरुग्नानम एस/ओ थिवुग्नानम और अन्य 2018 एससीसी ऑनलाइन कर 621।

प्रतिवादी संख्या 1 का तर्क यह है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की खंड 6 के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1, पिता होने के नाते , स्वाभाविक अभिभावक है

और अपीलकर्ताओं को बच्ची की अभिरक्षा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है और अभिरक्षा सौंपने से इनकार करना बच्ची को अवैध रूप से हिरासत में रखने के बराबर है और इसलिए , निवारण की मांग करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट उसके लिए उपलब्ध उचित उपाय था।

13. बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विषेषाधिकार प्रक्रिया है जिसके तहत विषय की स्वंतत्रता को सुरक्षित करके एक अवैध या अनुचित निरोध से तत्काल रिहाई का एक प्रभावी साधन प्रदान करता है। रिट एक नाबालिग की अभिरक्षा को उसके अभिभावक को बहाल करने के लिए भी अपना प्रभाव बढ़ाती है जब उसे गलत तरीके से वंचित कर दिया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग को अभिरक्षक हिरासत में लेना जो उसकी अभिरक्षा नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा अवैध हिरासत के बराबर माना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति द्वारा नाबालिग की अभिरक्षा की बहाली के लिए जो व्यक्तिगत कानून के अनुसार, उसका कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं है, उपयुक्त मामलों में, रिट अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है।

14. गौहर बेगम में , जहाँ माँ को व्यक्तिगत कानून के तहत , अपने अवैध नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा का कानूनी अधिकार था , रिट जारी की गई थी।गौहर बेगम में , सर्वोच्च न्यायालय ने एक अवैध बच्ची की वसूली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर सुनवाई की।

शोहर ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि गोहर की मां की बहन कनीज बेगम पर गोहर की नवजात बच्ची को अवैध रूप से हिरासत में ले रही थी।सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून के तहत इस स्थिति पर ध्यान दिया कि एक अवैध बच्ची की मां उसकी अभिरक्षा की हकदार है और बच्ची की अभिरक्षा को मां को बहाल करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप बच्ची की अवैध अभिरक्षा होगी।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कनिज को बच्ची की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और बच्ची को मां को सौंपने से इनकार करने के परिणामस्वरूप पुरानी संहिता की खंड 491

Cr.P.C के अर्थ में बच्ची को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह तथ्य कि गौहर को संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत अधिकार था , खंड 491 Cr.P.C के तहत अपने अधिकार से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गौहर बेगम , प्राकृतिक संरक्षक होने के नाते , रिट याचिका को बनाए रखने की हकदार हैं और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"7. इन निर्विवाद तथ्यों पर कानून की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है।इस मामले में लागू होने वाले मुस्लिम कानून के तहत , अपीलकर्ता अंजुम की अभिरक्षा का हकदार है, जो उसकी अवैध बेटी है, चाहे अंजुम का पिता कोई भी हो।प्रतिवादी को बच्ची की अभिरक्षा का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।इसलिए अपीलकर्ता को बच्ची को सौंपने से इनकार करने के परिणामस्वरूप खंड 491 के अर्थ में बच्ची को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया।शिशुओं के उपस्थिती के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेखों से संबंधित अंग्रेजी मामलों में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

क्वीन बनाम क्लार्क (1857) 7 ई. एल. और बी. एल. 186:119, ईआर 1217

लॉर्ड कैम्पबेल, सी. जे. ने पी. में कहा।193:

"लेकिन पालन-पोषण के लिए संरक्षकता के तहत एक बच्ची के संबंध में , बच्ची को अभिभावक की अभिरक्षा से गैरकानूनी रूप से अभिरक्षा में लिए जाने पर गैरकानूनी रूप से कैद किया जाना समझा जाएगा और जब उसे सौंप दिया जाता है , तो बच्ची को मुक्त समझा जाएगा।

हमारे देश की अदालतों ने लगातार यही दृष्टिकोण अपनाया है।इस उद्देश्य के लिए इसके बाद उद्धृत भारतीय मामलों को संदर्भित किया जा सकता है।खंड 491 की शर्तें स्पष्ट रूप से मामले पर लागू होंगी और अपीलकर्ता अपने द्वारा मांगे गए आदेश का हकदार होगा।

अदालत का विचार स्पष्ट रूप से गलत था कि बच्ची अंजुम को अवैध रूप से या अनुचित तरीके से हिरासत में नहीं लिया जा रहा था।विद्वान न्यायाधीशों ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया है और हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि यह कानून के दृष्टिकोण में अस्थिर है।

.....

10. हम आगे कोई कारण नहीं देखते हैं कि अपीलकर्ता को बच्ची की अभिरक्षा की वसूली के लिए संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत आगे बढ़ने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए था।निश्चय ही उसे ऐसा करने का अधिकार वा। लेकिन उसे संहिता की खंड 491 के तहत बच्ची की अभिरक्षा के आदेश का भी स्पष्ट अधिकार था।यह तथ्य कि उसे अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत अधिकार था , खंड 491 के तहत उसे अधिकार से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है।यह अच्छी तरह से स्थापित है जैसा कि इसके बाद उद्धृत मामलों से दिखाई देगा।(रेखांकित करना जोड़ा गया)

15. वीणा कपूर में, बच्चे की अभिरक्षा का मुद्दा उन स्वाभाविक अभिभावकों के बीच था जो एक साथ नहीं रह रहे थे। बच्ची की मां वीणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर अपने पति से बच्ची की अभिरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसके पति के पास डेढ़ साल के बच्ची की अवैध अभिरक्षा है।सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नीचे लें और इस सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट भेजें कि क्या नाबालिग बच्ची के हित को ध्यान में रखते हुए, उसकी मां को उसकी अभिरक्षा दी जानी चाहिए।

16. राजीव भाटिया बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और अन्य

(1999) 8 एस. सी. सी. 525, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लड़की की माँ प्रियंका द्वारा दायर की गई थी , जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी अपने पति के बड़े भाई राजीव की अवैध हिरासत में थी।राजीव एक दत्तक विलेख पर निर्भर था।प्रियंका ने दलील दी कि यह एक धोखाधड़ी वाला दस्तावेज था।उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को गोद लेने के विलेख की वैधता की जांच

करने और फिर बच्ची की अभिरक्षा के संबंध में किसी न किसी तरह से निष्कर्ष पर पहुंचने का अधिकार नहीं है।

17. मंजू मालिनी में जहाँ माँ ने अपने नाबालिग बच्ची तनिष्का की अभिरक्षा के लिए अपनी बहन और बहनोई से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी , जिसने बच्ची को माँ को सौंपने से इनकार कर दिया था , कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"24. जिस क्षण प्रतिवादी 1 और 2 ने नाबालिग तनिष्का की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को प्राकृतिक और कानूनी अभिभावक को सौंपने से इनकार कर दिया , उनके साथ उसकी अभिरक्षा जारी रखना अवैध निरोध बन जाता है।प्रतिवादी Nos.1 और 2 की ओर से इस तरह का जानबूझकर किया गया कार्य भा .दं.सं. सी. के S.361 के तहत दंडनीय अपहरण के अपराध के बराबर है। इसलिए इस तर्क में कोई योग्यता नहीं है कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है और प्रतिवादी नं.1 और 2 बच्ची तनिष्का की कानूनी हिरासत में हैं।

18. बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही अभिरक्षा की वैधता को उचित ठहराने या जांच करने के लिए नहीं है।बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही एक ऐसा माध्यम है जिस के **द्वारा से** बच्ची **की अभिरक्षा को अदालत के विवेक के अनुसार संबोधित किया जाता है।बंदी प्रत्यक्षीकरण एक विशेषाधिकार रिट है जो एक असाधारण उपाय है और रिट जारी की जाती है जहां विशेष मामले की परिस्थितियों में, कानून द्वारा प्रदान किया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है; अन्यथा एक रिट जारी नहीं की जाएगी।बाल अभिरक्षा मामलों में, रिट देने में उच्च न्यायालय की शक्ति केवल उन मामलों में योग्य है जहां किसी नाबालिग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हिरासत में लिया जाता है जो अपनी कानूनी अभिरक्षा का हकदार नहीं है।सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रश्नगत मुद्दे पर दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, बाल अभिरक्षा मामलों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है जहां यह साबित हो जाता है कि माता-पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग** बच्ची **को हिरासत में रखना अवैध था और बिना किसी कानून के अधिकार के था।**

19. बाल अभिरक्षा मामलों में , सामान्य उपाय केवल हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम या अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत निहित है , जैसा भी मामला हो।अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामलों में , अदालत का अधिकार क्षेत्र इस बात से निर्धारित होता है कि क्या नाबालिग सामान्य रूप से उस क्षेत्र के भीतर रहता है जिस पर अदालत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करती है।अभिभावक और वार्ड अधिनियम के तहत जांच और एक रिट अदालत द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो संक्षिप्त प्रकृति का है।जो महत्वपूर्ण है वह है बच्ची का कल्याण।रिट अदालत में , अधिकारों का निर्धारण केवल शपथ पत्रों के आधार पर किया जाता है।जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, वहां अदालत राशनीत कौर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

419

असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं और पक्षों को दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दे सकते हैं।यह केवल असाधारण मामलों में है , नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए एक याचिका पर असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

20. वर्तमान मामले में , अपीलकर्ता माँ ज़ेलम की बहनें और भाई हैं जिनके पास नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।जबकि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम की खंड 6 के अनुसार, पहला प्रतिवादी-पिता नाबालिग बच्ची का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे बच्ची की अभिरक्षा का दावा करने का कानूनी अधिकार है। बच्ची की अभिरक्षा के लिए पिता की पात्रता विवादित नहीं है और डेढ़ साल की उम्र का बच्चा अपनी बुद्धिमान प्राथमिकताओं को व्यक्त नहीं कर सकता है।इसलिए , हमारे विचार में , इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में , पिता, स्वाभाविक अभिभावक होने के नाते , भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के

तहत बच्ची की अभिरक्षा की मांग करने वाले असाधारण उपाय का आह्वान करना उचित था।

21. बच्ची की अभिरक्षा विदेशों से हटाकर भारत लाई गईः- कई सारे निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने उस देश में अदालत द्वारा हिरासत के प्रश्न पर संक्षिप्त या विस्तृत जांच के संचालन पर विचार किया , जिसमें बच्ची को हटा दिया गया है।कई निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उसके समक्ष दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर विचार किया, उस बच्ची की अभिरक्षा के सवाल पर जिसे विदेशों से हटा दिया गया था और भारत लाया गया था और नाबालिग बच्चों को उस देश में वापस भेजने के सवाल पर जहां से उन्हें माता -पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा हटा दिया गया था।कई मामलों में , सर्वोच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि उच्च न्यायालय निरोध की वैधता निर्धारित करने के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है।हालांकि , अदालत ने यह विचार रखा है कि विदेशी अदालत का आदेश बच्ची के कल्याण के लिए होना चाहिए।विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, रुचि माजू बनाम.

संजीव माजू (2011) 6 एस. सी. सी. 479, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

“58. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में कार्यवाही 420 है।

सारांश प्रकृति में, जहां कथित बंदी की नजरबंदी की वैधता की जांच पक्षों द्वारा दिए गए हलफनामों के आधार पर की जाती है।फिर भी , कुछ भी उच्च न्यायालय को उन मामलों में विस्तृत जांच शुरू करने से नहीं रोकता है जहां नाबालिग का कल्याण प्रश्नगत है, जो अपने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार है।इसलिए , उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले

मामलों में निरोध की वैधता निर्धारित करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है और नाबालिग की अभिरक्षा के बारे में आदेश भी जारी कर सकता है , जो इस बात पर निर्भर करता है कि अदालत ऐसी अभिरक्षा के लिए प्रतिद्वंद्वी दावों, यदि कोई हो, को कैसे देखती है।

59.न्यायालय नाबालिग बच्ची को उस देश में वापस भेजने का भी निर्देश दे सकता है जहाँ से उसे माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया गया हो; जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था।

रवि चंद्रन 2009 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 961:(2010) 1 एस. सी. सी. 174 और शिल्पा अग्रवाल, 2010 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 331:

(2010)1 एस. सी. सी. 591 मामले या ऐसा करने से इनकार जैसा कि था

सरिता शर्मा मामला 2000 (2) आरसीआर (सिविल) 367 में स्थितिः

(2000)3 एससीसी 14.महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक कथित बंदी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तब तक उचित आदेश पारित करने की उसकी क्षमता का कोई सवाल ही नहीं उठता है।हिरासत के संबंध में उचित आदेश देने के लिए रिट अदालत का अधिकार क्षेत्र जल्द ही उत्पन्न होता है जब यह पाया जाता है कि कथित बंदी उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में है।"

22. विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए भारत लाए गए नाबालिग बच्ची के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, नित्या आनंद राघवन बनाम

v. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) मामले में (2017) 8 एस. सी. सी. 454 के रूप में आयोजित किया गया था

इसके अंतर्गतः-

“46. उच्च न्यायालय एक नाबालिग बच्ची के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की याचिका पर विचार करते समय , किसी मामले में , बच्ची की वापसी का निर्देश दे सकता है या ऊपर उल्लिखित तय कानूनी स्थिति सहित सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्ची की अभिरक्षा को बदलने से इनकार कर सकता है।एक बार फिर, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि अदालत का निर्णय, प्रत्येक मामले में, और अन्य के कल्याण पर विचार करते हुए उसके सामने लाए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर निर्भर होना चाहिए।

बच्चा जो सर्वोपरि विचार का विषय हो।विदेशी अदालत का आदेश बच्ची के कल्याण के लिए होना चाहिए।इसके अलावा , बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के उपाय का उपयोग विदेशी अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति के खिलाफ दिए गए निर्देशों को केवल लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है और उस अधिकार क्षेत्र को निष्पादन अदालत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।निर्विवाद रूप से , रिट याचिकाकर्ता विदेशी न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने के लिए या बच्ची की अभिरक्षा के लिए भारतीय न्यायालय के समक्ष किसी अन्य कार्यवाही का सहारा लेने के लिए ऐसे अन्य उपाय का सहारा ले सकता है जो कानून में अनुमत हो।

23. सरिता शर्मा में, दो नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा को लेकर झगड़ा उनकी अलग हुई माँ और पिता के बीच था।संयुक्त राज्य अमेरिका के परिवार न्यायालय ने तलाक की डिक्री पारित करते हुए पिता को अभिरक्षा का अधिकार दिया।जब माँ बच्चों के साथ भारत आई, तो पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने माँ को पिता को अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया।उच्चतम न्यायालय ने अपील में कहा कि उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अनुमति देने के बजाय पक्षों को उचित कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देना चाहिए था जिसमें बच्चों के हित की गहन जांच की जा सके।

24. हाल के निर्णय में लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली

सोभन कोडाली 2019 (5) स्केल 97, इस अदालत ने संदर्भित किया

नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में सभी निर्णय जब माता -पिता अनिवासी (एन. आर. आई.) हों।हमने विदेश से हटाए गए और पूरा करने के लिए भारत लाए गए बच्ची बच्ची की अभिरक्षा से संबंधित उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया है और यह इंगित करने के लिए कि अब तक विदेशों से हटाए गए और भारत लाए गए बच्चों में महत्वपूर्ण अंतर है।

25. नाबालिग बच्ची **का कल्याण सर्वोपरि विचार हैः- बाल अभिरक्षा मामलों का निर्णय करते समय अदालत केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बंधी नहीं होती है।यद्यपि विशेष कानूनों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग** बच्ची **की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में नाबालिग का कल्याण सर्वोच्च विचार है।न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार होना चाहिए।**

बच्चों का हित और कल्याण होना।

26. नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंनु, 2008 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 936(2008)9 SCC 413: कई निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि बाल अभिरक्षा मामलों से निपटने के दौरान, बच्ची **के कल्याण पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए और** बच्ची **के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-**

“49. गोवर्धन लाल बनाम गजेंद्र कुमार, आकाशवाणी 2002

राज 148 में उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि पिता एक नाबालिग बच्ची का स्वाभाविक अभिभावक है और इसलिए उसे अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करने का अधिमानी अधिकार है , लेकिन एक नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है न कि किसी विशेष पक्ष का

कानूनी अधिकार।1956 के अधिनियम की खंड 6 इस प्रमुख विचार का स्थान नहीं ले सकती है कि नाबालिग बच्ची के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।यह भी देखा गया कि एकमात्र विचार के रूप में बच्ची के कल्याण को ध्यान में रखते हुए , बच्ची की इच्छाओं का पता लगाना उचित होगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है।

50. पुनः, एम. के. हरि गोविंदन बनाम ए. आर. राजाराम, आकाशवाणी

2003 मद्रास 315 में न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि अभिरक्षा मामलों का निर्णय मानव स्पर्श के संदर्भ के बिना दस्तावेजों, मौखिक साक्ष्य या पूर्व निर्णय पर नहीं किया जा सकता है।नाबालिग के कल्याण के लिए मानवीय स्पर्श प्राथमिक है क्योंकि अन्य सामग्री या तो मुकदमों द्वारा स्वयं या उनकी सुविधा के अनुरूप वकील की सलाह पर बनाई जा सकती है।

51. कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1987 हिमाचल

प्रदेश 34 न्यायालय ने कहाः

"13..... न्यायालय अपने अंतर्निहित और सामान्य अधिकार क्षेत्र में बाल अभिरक्षा मामलों का निर्णय करते समय माता-पिता या अभिभावक के केवल कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है।यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है , लेकिन ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले अपने माता -पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्ची के सामान्य आराम , संतुष्टि, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक जैसी परिस्थितियों को उचित महत्व देता हो।

विकास, उसका स्वास्थ्य , शिक्षा और सामान्य रखरखाव और अनुकूल परिवेश।इन मामलों का निर्णय अंततः उस बच्ची के सर्वोत्तम हितों के न्यायालय के दृष्टिकोण पर किया जाना चाहिए जिसके कल्याण के लिए आवश्यक है कि वह माता -पिता में से किसी एक या दूसरे की अभिरक्षा में हो।"

52. हमारे निर्णय में, एक बच्ची की अभिरक्षा से संबंधित कानून काफी अच्छी तरह से तय किया गया है और यह है:नाबालिग की अभिरक्षा के बारे में एक कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय लेने में , एक अदालत को प्रासंगिक कानूनों और उनसे प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए।लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता है।यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानव स्पर्श से हल करने की आवश्यकता है।अभिरक्षा मामलों से निपटने के दौरान एक अदालत न तो कानूनों से बंधी होती है और न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से और न ही पूर्व निर्णय नियमों से।नाबालिग के उचित अभिभावक का चयन करने में , बच्ची का कल्याण और कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए।अभिभावक के चयन में , न्यायालय माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और बच्ची के सामान्य आराम , संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देने के लिए बाध्य है।लेकिन शारीरिक आराम से ऊपर, नैतिक और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं , और भी अधिक महत्वपूर्ण , आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं।यदि नाबालिग एक बुद्धिमान वरीयता या निर्णय बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो अदालत को इस तरह की प्राथमिकता पर भी विचार करना चाहिए , हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के पास होना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।"

27. भरोसा गौरव नागपाल बनाम सुमेधा

नागपाल (2009) 1 एस. सी. सी. 42 पर भरोसा किया गया**, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-**

32. मैकग्राथ (1893) 1 Ch 143 में, लिंडले, एल. जे. ने कहा:(अध्याय 148) न्यायालय के विचार के लिए प्रमुख मामला बच्ची का कल्याण है।लेकिन बच्ची के कल्याण को केवल धन से नहीं मापा जाना चाहिए और न ही केवल शारीरिक आराम से।कल्याण शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्ची के नैतिक या धार्मिक कल्याण के

साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए।न ही स्नेह के बंधन की उपेक्षा की जा सकती है।

(जोर दिया गया)

50. जब अदालत को माता -पिता द्वारा की गई परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है, तो हर बार उसे मांगों को उचित ठहराना पड़ता है।अदालत को इस मुद्दे को न केवल कानूनी आधार पर देखना है , बल्कि ऐसे मामलों में उन मुद्दों को तय करने के लिए मानवीय कोण भी प्रासंगिक हैं।अदालत तब इस बात पर जोर नहीं देती है कि पक्ष क्या कहते हैं , उसे एक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना पड़ता है जिसका उद्देश्य नाबालिग के कल्याण के लिए होता है।जैसा कि हाल ही में मौसमी

मोइत्रा गांगुली मामला 2008 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 551:(2008) 7

एस. सी. सी. 673, न्यायालय को बच्ची की सामान्य संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देना होगा , लेकिन शारीरिक सुख - सुविधाओं के अलावा, नैतिक और नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना होगा।वे बराबर हैं, यदि दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं।

51. अधिनियम की खंड 13 में उपयोग किए गए कल्याण शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्ची के नैतिक और नैतिक कल्याण को अदालत के साथ -साथ उसके शारीरिक कल्याण के साथ भी तौलना चाहिए।यद्यपि माता -पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष कानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले अपने माता -पिता के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के रास्ते में खड़ा हो सकता है।

28. यह तर्क देते हुए कि पक्षकारों के दावे हालांकि वैध हैं , वे बच्चे के हित और कल्याण के अधीन हैं

रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल, (1973) 1

एस. सी. सी. 840 में, इस न्यायालय ने कहा है किः-

"7 जिस सिद्धांत पर अदालत को अभिभावक की योग्यता का फैसला करना चाहिए , वह मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता हैः ((i) पिता की संरक्षक होने की योग्यता या अन्यथा, और (ii) नाबालिगों के हित।

"15. ..... बच्चे केवल चल-सम्पत्ति नहीं हैंः न ही वे अपने माता-पिता के लिए केवल एक खेलने की चीज हैं। माता-पिता का अपने बच्चों के भाग्य और जीवन पर आत्यन्तिक अधिकार, आधुनिक परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में , मनुष्य के रूप में उनके कल्याण के विचारों के आगे झुक गया है ताकि वे सामान्य रूप से संतुलित तरीके से बड़े होकर समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें और अन्य मामलों में संरक्षक न्यायालय बन सकें।

माँ और पिता के बीच विवाद, नाबालिग बच्चों के कल्याण की आवश्यकताओं और उन पर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकारों के बीच एक न्यायपूर्ण और उचित संतुलन बनाने की उम्मीद है।विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण , हमारे विचार में , सही था और हम उनसे सहमत हैं।अपील पर हमें ऐसा लगता है कि 11 की लेटर्स पेटेंट पीठ ने उन्हें उन आधारों पर उलटने में गलती की है जिनकी हम सराहना करने में असमर्थ हैं।

29. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने

जी. ईवा मैरी एलेजाबथ बनाम जयराज 2005 एससीसी ऑनलाइन मैड 472 पर विष्वास जताया है जहां की अभिरक्षा

एक महीने की उम्र का नाबालिग बच्चा, जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद पिता ने चर्च परिसर में छोड़ दिया था , सवाल में था।तदनुसार बच्ची की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंप दी गई , जिसने चर्च के पादरी द्वारा ढाई साल तक बच्ची की देखभाल की।पिता ने ढाई साल बाद याचिकाकर्ता की हिरासत से बच्ची को छीन

लिया। बच्ची के पिता, जिन्होंने बच्ची को स्वाभाविक अभिभावक के रूप में छोड़ दिया है, को हिरासत में लेने से मना कर दिया गया था।

30. कीर्ति कुमार महेषंकार जोषी बनाम प्रदीप कुमार करूणा शंकर जोषी **1993 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 529:(1992) 3 एस. सी. सी. 573,** में **बच्चों के पिता भा.दं.सं. सी. की खंड 498-ए के तहत आरोप का सामना कर रहे थे और बच्चों ने अपने मामा के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की जो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे और बच्चों ने अपने पिता के साथ नहीं जाने की इच्छा व्यक्त की।सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों को उनकी भलाई को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान पाया और मामले की परिस्थितियों में, हिरासत को उनके पिता के बजाय मामा को सौंप दिया।**

31. हाल के मामले में , पिता एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक है जो जीवित है और उसने न तो बच्ची को छोड़ा है और न ही उसकी उपेक्षा की है।केवल मामले की विषम परिस्थितियों के कारण , अपीलार्थियों द्वारा बच्ची की देखभाल की गई थी।इसलिए , अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामले तथ्यों के आधार पर अलग -अलग हैं और पिता को बच्ची की अभिरक्षा से इनकार करने के लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं।

33. जैसा कि रोजी जैकब में पहले देखा गया है , पिता की फिटनेस पर विचार किया जाना चाहिए और नाबालिक बच्चे के कल्याण के लिए मुख्य रूप से, निर्धारित किया जाना चाहिए

मुख्य रूप से सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के संदर्भ में अपने नाबालिग बच्चों के कल्याण के संदर्भ में जोर देना चाहिए। बच्ची के कल्याण में नैतिक पालन -पोषण, अभिभावक का आर्थिक कल्याण , बच्ची का सामान्य आराम , संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल होंगे। बच्चा शिखा ने अपनी माँ को खो दिया जब वह सिर्फ चौदह महीने की थी और अब बिना किसी वैध कारण के अपने पिता के प्यार से वंचित हो रही है।जैसा कि उच्च न्यायालय ने बताया है , पिता एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर काम कर रहे हैं।उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर है।

34. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण बच्ची के कल्याण का निर्धारण किया जाना चाहिए और अदालत एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है।वर्तमान मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने न तो बच्ची को छोड़ा है और न ही बच्ची को उसके प्यार और स्नेह के अधिकार से वंचित किया है।परिस्थितियां ऐसी थीं कि माता - पिता की बीमारी के कारण अपीलकर्ताओं को कुछ समय के लिए बच्ची की देखभाल करनी पड़ी।केवल इसलिए कि रिश्तेदार होने के नाते अपीलकर्ता कुछ समय के लिए बच्ची की देखभाल करते थे , वे बच्ची की अभिरक्षा को बनाए नहीं रख सकते।यह अपीलार्थियों का मामला नहीं है कि पहला प्रतिवादी बच्ची की देखभाल करने के लिए अयोग्य है, सिवाय इस तर्क के कि उसके पास बच्ची की देखभाल करने के लिए कोई महिला समर्थन नहीं है।पहला प्रतिवादी अपनी बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब स्वस्थ है और उसे अपनी माँ का समर्थन प्राप्त है और वह बच्ची की देखभाल करने में समर्थ है।

मंदीप कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य में। जहाँ

माँ ने नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा के लिए पिता के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, इस अदालत ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

11. यह प्रश्न जो सबसे पहले उठता है कि क्या वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रतिवादी संख्या 4 पिता, जो एच. एम. जी. अधिनियम की खंड 6 के तहत उसके स्वाभाविक अभिभावक हैं, के साथ नाबालिग बेटी की अभिरक्षा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी है, अवैध नहीं है और संरक्षक/परिवार न्यायालय के समक्ष एच. एम. जी. अधिनियम/जी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत नाबालिग बेटी की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर करने के वैकल्पिक उपाय की याचिकाकर्ता को उपलब्धता है।

12. अब, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कर सकती है

नाबालिग की अभिरक्षा को गलत तरीके से वंचित अभिभावक को बहाल करने के लिए जारी किया जाए।

13. 2020 एसएलपी (सी. आर. एल.) दाण्डिक अपीलीय सं 127 में 2019 की संख्या 7390 का शीर्षक यशिता साहू बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य ने 20.01.2020 पर निर्णय लिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"9. यह आग्रह करने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है कि यदि बच्चा किसी अन्य माता-पिता की अभिरक्षा में है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट बनाए रखने योग्य नहीं है।इस संबंध में कानून ने समय के साथ बहुत कुछ विकसित किया है, लेकिन अब यह एक तय स्थिति है कि अदालत बच्ची **के सर्वोत्तम हित के लिए अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकती है।यह एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ और अन्य में किया गया है। (1987) 1 एस. सी. सी. 42, नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य (2017) 8 एस. सी. सी. 454 और लहरी सखामुरी बनाम सोभन कोडाली (2019) 7 एस. सी. सी. 311 आदि।इन सभी मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार किया गया।इसलिए, हम अपीलकर्ता पत्नी के इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका विचारणीय नहीं थी।"**

14. ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न केवल हिरासत की अवैधता के निर्धारण पर निर्भर है और जरूरी नहीं कि यह माता-पिता के कानूनी अधिकारों की परवाह किए बिना नाबालिग बच्ची **के कल्याण के सर्वोपरि विचार पर आधारित है।**

20. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि यदि नाबालिग बच्चा अवैध हिरासत में है या हिरासत में रखा गया है जो नाबालिग बच्ची के हित के लिए हानिकारक होगा, तो नाबालिग बच्ची की हिरासत की वसूली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए एक याचिका विचारणीय है।

बेगम गौहर बनाम सुग्गी उपनाम नजमा बेगम (1960) 1 एस. सी. सी. 597; मंजू तिवारी बनाम राजेंद्र तिवारीःए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1156; सैयद सलीमुद्दीन

बनाम डॉ. रुखसाना:2001(2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 591 और तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम। शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य (एससी):

2019(3) आर. सी. आर. (सिविल) 104.)उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32/226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके निर्देश दे सकता है कि नाबालिग की अभिरक्षा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाए।

कानून के अनुसार संरक्षक/परिवार न्यायालय द्वारा उसकी अभिरक्षा के प्रश्न के निर्णय तक।(मंजू तिवारी बनाम डॉ . राजेंद्र तिवारी, (एससी) देखें।ए. आई. आर 1990 एस. सी. 1156; सैयद सलीमुद्दीन बनाम डॉ . रुखसाना 2001 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 591; रोक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा (एससी):2015 (2) आर. आर. (सिविल) 93; गिप्पी अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य और अन्यः 2012(4) आर. आर. (सिविल) 397 (पी. एच. एच. सी.); 2017 का सी. आर. डब्ल्यू. पी. No.68 शीर्षक 'किरणदीप कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य ' ने 'आई. डी. 2' और 2020 का सी. आर. डब्ल्यू. पी.-3013 शीर्षक 'नेहा बनाम हैरान राज्य और अन्य' ने 'आई. डी. 3' पर निर्णय लिया।)एच. एम. जी. अधिनियम/जी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत हिरासत याचिका दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता हीबियस कॉर्पस की रिट जारी करने के लिए असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई बाधा नहीं है।(गौहर बेगम बनाम सुग्गी उपनाम नजमा बेगम (1960) 1 एस. सी. सी. 597; तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य (एससी):2019(3) आर. आर. (सिविल) 104; श्रीमती. नंदिता विरमानी बनाम रमन विरमानीः1983 क्राई। एल. जे. 794 और दुर्गेश कुमार आहूजा बनाम। विनीत खुराना और एकः1985 क्राई। एल. जे. 1195)

21. जहाँ तक उत्तरदाताओं के लिए संख्या 4 और 5 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निर्णयों का संबंध है, अमित बनाम

निर्मल साहू (इलाहाबाद उच्च न्यायालय):2009(5) आर. सी. आर. (सिविल) 258 में

आवेदक माँ द्वारा एक झूठा दावा किया गया था कि उसे 10-7-2007 पर अपने पति के घर से बाहर निकाल दिया गया था।रिकॉर्ड ने संकेत दिया कि आवेदक ने बच्ची के जन्म के लगभग एक महीने बाद 20-11-2005 पर अपने पति का घर छोड़ दिया।विरोधी पक्ष ने हिंदू विवाह अधिनियम , 1955 की खंड 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसमें आवेदक ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की खंड 24 के तहत रिट याचिका दायर करने से पहले भरण-पोषण के अनुदान के लिए आवेदन दायर किया था।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि लड़के के पिता और प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बच्ची को कथित रूप से हिरासत में रखना न तो अवैध था और न ही कानून के किसी अधिकार के बिना था और माँ को एच . एम. जी. अधिनियम की खंड 6 के तहत आवेदन करना चाहिए था क्योंकि मामला परिवार के समक्ष लंबित था।

अदालत।मंजुला झा बनाम रवींद्र नाथ झा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय):1988(1) याचिकाकर्ता ने एचएलआर 273 में दायर किया था। याचिकाकर्ता ने अभिभावक खंड के 10 के तहत एक आवेदन

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

छह वर्ष की आयु के बेटे की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले जिला न्यायाधीश , अलीगढ़ की अदालत में वार्ड अधिनियम , 1890।चूंकि याचिकाकर्ता वास्तव में वैकल्पिक उपचार का लाभ उठा रहा था , इसलिए न्यायालय ने कहा कि नाबालिग के कल्याण के संबंध में मामले की उचित और प्रभावी रूप से जिला न्यायाधीश द्वारा जांच और निर्णय लिया जा सकता है , जिनके समक्ष संरक्षक और वार्ड अधिनियम , 1890 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता का आवेदन लंबित था।मुथियान

शिवथानु बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य (मद्रास उच्च न्यायालय):2014(38)

आर. सी. आर. (आपराधिक) 219 में जहाँ बच्ची की अभिरक्षा की मांग करते हुए 2011 का जी. डब्ल्यू. ओ. पी. सं. 2177 दायर किया गया था और वही परिवार न्यायालय, चेन्नई के समक्ष लंबित था , पिता द्वारा माँ के साथ बच्ची की अभिरक्षा के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।इन सभी मामलों में मुकदमेबाजी -वैवाहिक या अभिरक्षा याचिका पहले से ही परिवार /संरक्षक न्यायालय के समक्ष लंबित थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को अस्वीकार करने में विचार में लिया गया था।वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त संदर्भित मामलों से अलग हैं क्योंकि याचिकाकर्ता वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले ऐसा कोई उपाय नहीं कर रहा था।इसके अलावा , सैयद मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए

सलीमउद्दीन बनाम डॉ. रुखसाना 2001 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 591 और वीणा कपूर बनाम वरिंदर कुमार कपूरःए. आई. आर. 1982 सुप्रीम कोर्ट 792,

बंदी-अलीज़ेह ढल्ला की अभिरक्षा के सवाल का फैसला उसके कल्याण के सर्वोपरि विचार पर किया जाना है।इसलिए, अमित बनाम निर्मल साहू में टिप्पणियाँ

(लखनऊ बेंच):2009(5) आर. सी. आर (सिविल) 258; मंजुला झा बनाम रवींद्र नाथ झा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय):1988(1) एचएलआर 273 और मुथियान शिवथानु बनाम गृह सचिव, तमिलनाडु सरकार और अन्य (मद्रास उच्च न्यायालय):2014(38) आर. सी. आर. (आपराधिक) 219 विद्वान वकील प्रतिवादी नं. 4 और 5 निर्भर करते हुए प्रतिवादी नं. 4 व 5 के लिए कोई मददगार नही हैं।

22. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नाबालिग बेटी की अभिरक्षा के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसमें प्रतिवादी नं. 4 पिता **अवैध नहीं है और उपलब्धता है।**

एच. एम. जी. अधिनियम/जी. डब्ल्यू. अधिनियम के तहत अभिरक्षा याचिका दायर करने के वैकल्पिक उपाय के याचिकाकर्ता को।

23. इसके बाद जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 से नाबालिग बेटी की अभिरक्षा लेने का हकदार है।

24. हिंदू पक्षों के बीच, एच. एम. जी. अधिनियम उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जिन पर हिरासत विवादों का निर्णय लिया जाना है।एच . एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए) के अनुसार, नाबालिग व्यक्ति के साथ -साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग का स्वाभाविक अभिभावक पिता होता है , लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में और उसके बाद माँ।हालांकि , एच. एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए) के प्रावधान में कहा गया है कि पांच साल की उम्र पूरी नहीं करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर मां के पास होगी।

25. रोक्सन शर्मा बनाम अरुण शर्मा (एससी):2015 (2)

आर. सी. आर (सिविल) 93 में **माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-**

“12. एच. एम. जी. अधिनियम में कहा गया है कि एक शिशु या एक कम उम्र के बच्ची की अभिरक्षा उसकी माँ को दी जानी चाहिए जब तक कि पिता ठोस कारणों का खुलासा नहीं करता है जो बच्ची के कल्याण और हित की आजीविका को कम करने या खतरे में डालने का संकेत देते हैं।एच . एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए), इसलिए, नाबालिग बच्ची की संपत्ति के संरक्षक होने के पिता के अधिकार को संरक्षित करती है, लेकिन अपने व्यक्ति के अभिभावक नहीं, जबकि बच्चा पांच साल से कम उम्र का है।यह संरक्षकता के विपरीत , अंतरिम अभिरक्षा के अपवाद को स्पष्ट करता है , और फिर निर्दिष्ट करता है कि अभिरक्षा माँ को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि बच्चा पाँच साल से कम उम्र का हो।हमें तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि यह खंड या उस मामले के लिए जी एंड डब्ल्यू अधिनियम में निहित प्रावधानों सहित कोई अन्य प्रावधान , मां

को बच्ची की पांच साल की उम्र पार करने के बाद भी उसकी अभिरक्षा के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है।"

26. 2020 के सी. आर. डब्ल्यू. पी.-3013 में 'नेहा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' शीर्षक से 01.06.2020 पर निर्णय लिया गया जबकि

एच. एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए) की व्याख्या करते हुए , एक समन्वित और अन्य

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

इस न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"13. .....इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रावधान यह मानता है कि अभिरक्षा "आम तौर पर" मां के पास होगी।लेकिन "साधारण रूप से" शब्द का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि जब तक, प्रथमदृष्टया, यह पिता द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया जाता है कि मातृत्व से वंचित होने से बच्ची की बेहतर देखभाल की जा सकती है।फिर पिता को कुछ ठोस कारण देने चाहिए , जो बच्ची के कल्याण और हित को खतरे में डालने का संकेत देते हैं या विशेष रूप से मातृत्व के बाल आत्मा के पालन -पोषण के लिए आसन्न रूप से गैर-अनुकूल होने का संकेत देते हैं।

खंड 6 की परिकल्पना यह है कि , नाबालिग की कम उम्र को देखते हुए , अभिरक्षा की उपयुक्तता प्रमुख कारक नहीं है, जो अधिक प्रासंगिक है या जिसे दबाव देना चाहिए, वह आवश्यक जैविक और प्राकृतिक वातावरण है , जो एक सामान्य धारणा को जन्म देता है कि माँ उस उम्र के नाबालिग की देखभाल के लिए सबसे पहले और सबसे उपयुक्त है।"

27. वर्तमान मामले में नाबालिग बेटी के कल्याण और हित के सवाल का फैसला मां के सहज निस्वार्थ प्रेम और अपने बच्चों, विशेष रूप से शिशुओं के प्रति स्नेह की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत श्रेष्ठता पर विचार करने पर किया जाना चाहिए।माँ की

गोद प्राकृतिक पालना है जहाँ शिशु की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है।शिशु के लिए माँ की सुरक्षा अपरिहार्य है और कोई अन्य सुरक्षा उसके माप और सार के बराबर नहीं होगी।माँ के प्यार और देखभाल से माँ जैसी कोई संपत्ति या माँ नहीं हो सकती है।शिशुओं के स्वस्थ विकास के लिए माता की देखभाल और स्नेह अपरिहार्य है।

29. एच. एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए) को ध्यान में रखते हुए , नाबालिग बेटी की अभिरक्षा, जिसकी उम्र अब लगभग साढ़े तीन साल है , "सामान्य रूप से " होनी चाहिए और याचिकाकर्ता उसकी मां होनी चाहिए।नाबालिग बेटी की अभिरक्षा याचिकाकर्ता के पास तब तक थी जब तक कि प्रतिवादी संख्या 4 के कहने पर उसके और उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज चोरी के मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो गई।उपरोक्त चोरी के मामले में याचिकाकर्ता के अपराध या निर्दोष होने के सवाल का फैसला निचली अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले सबूत के आधार पर किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में इस अदालत द्वारा इस मामले में जाने की आवश्यकता नहीं है।याचिकाकर्ता का

उसके पिता के खिलाफ दर्ज किए गए आपराधिक मामलों से कोई लेना–देना नही है उसके भाई का उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद भी एक व्यक्तिगत मामला होगा। यह यहाँ अवलोकन करने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता को इन मामलों से नाबालिग बेटी की उचित देखभाल और मातृ देखभाल करने से अक्षम नहीं कहा जा सकता है।प्रतिवादी संख्या 4 व्यवसायी होने के नाते व्यवसाय में भाग लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को नाबालिग बच्ची की देखभाल करने के लिए उसकी माँ -याचिकाकर्ता की तुलना में बेहतर स्थिति में नहीं कहा जा सकता है।प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने नाबालिग बेटी के कल्याण और हित को खतरे में डालने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिए हैं , जो अपनी अंतरिम अभिरक्षा को अपनी मां को सौंपने या मां की अभिरक्षा को नाबालिग बेटी के उचित

पालन-पोषण, विकास और विकास के लिए गैर -अनुकूल होने का संकेत देते हैं।इसलिए, नाबालिग बेटी की अंतरिम अभिरक्षा से इनकार करने का कोई वैध आधार नहीं है, जिसकी आयु पांच साल से कम है, उसकी माँ-याचिकाकर्ता जो वास्तव में कल्याण के लिए और नाबालिग बेटी के सर्वोत्तम हित में आवश्यक है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 4 के साथ नाबालिग बेटी की अभिरक्षा , जो उसका पिता होने के नाते उसका स्वाभाविक अभिभावक है , को अवैध नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नाबालिग बेटी के पांच साल से कम होने के कारण , मां न केवल एच. एम. जी. अधिनियम की खंड 6 (ए) द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार के अनुसार इसकी अभिरक्षा की हकदार है, बल्कि यह भी कि यह कल्याण के लिए और नाबालिग बेटी के सर्वोत्तम हित में आवश्यक है।मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि जब तक नाबालिग बेटी की अभिरक्षा का सवाल अभिभावक/परिवार न्यायालय द्वारा तय नहीं किया जाता है , तब तक नाबालिग बच्ची के कल्याण और हित को उसकी अंतरिम अभिरक्षा उसकी माँ -याचिकाकर्ता को सौंपकर बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा।

नेहा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में। 3 जहाँ

माँ ने अपनी नाबालिग बेटी की अभिरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसे पिता द्वारा ले जाया गया था, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

“1. यह आपराधिक रिट याचिका सुश्री नेहा ने अपनी नाबालिग बेटी, लगभग 4 साल की त्रिशा की अभिरक्षा के लिए दायर की है, जिसे कथित तौर पर उसका पिता गुप्त तरीके से अपने साथ ले गया था।

5. प्रतिवादी नं. 4, पति ने अपनी वापसी में याचिका के कथनों का खंडन किया है।उन्होंने स्वीकार किया कि नाबालिग बच्चा 16.11.2019 के बाद से उनकी हिरासत में है, लेकिन आग्रह किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के माध्यम से हस्तक्षेप का

दायरा अवैध हिरासत के मामलों तक ही सीमित है।पिता होने के नाते , प्रतिवादी नं. 4 ने तर्क दिया कि किसी भी तरह से , उसे अपनी नाबालिग बेटी की गैरकानूनी हिरासत में नहीं कहा जा सकता है।उनके अनुसार , बच्चा उनकी हिरासत में है क्योंकि याचिकाकर्ता ने उन दोनों को छोड़ दिया है।उक्त परित्याग के बाद से , वह बच्ची और उसके कल्याण की उचित देखभाल कर रहा है , जो सर्वोपरि विचार का विषय है और 1890 के अधिनियम के तहत एक याचिका भी दायर की है। 8. इस सीमा पर, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है, क्योंकि बच्ची की उसके जैविक पिता के साथ अभिरक्षा को कल्पना के किसी भी विस्तार से अवैध नहीं माना जा सकता है।इसलिए , इस न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए।रिट याचिका की स्थिरता पर भी इस आधार पर आपत्ति जताई गई है कि दोनों पक्षों के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।जहाँ तक , संरक्षक/दीवानी न्यायाधीश, डेरा बस्सी नाबालिग बेटी की हिरासत के विवाद में पहले से ही पकड़े गए हैं।पिता पहले ही 1890 अधिनियम की खंड 25 के तहत एक याचिका दायर कर चुके हैं, जिसमें स्थायी हिरासत की मांग की गई है।प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील बताते हैं कि याचिकाकर्ता ने अभिरक्षा मामले में उपस्थिति दर्ज कराई है और नाबालिग बेटी की अंतरिम अभिरक्षा के लिए कोई आवेदन दायर नहीं करना पसंद किया है।इसलिए, अपनी सहमति से, ऐसा लगता है कि वह संबंधित न्यायालय द्वारा स्थायी अभिरक्षा के संबंध में अंतिम निर्णय दिए जाने तक बच्ची की पिता के साथ रहने की अंतरिम अभिरक्षा के लिए सहमत हो गई है।

9. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि नाबालिग बेटी की कम उम्र को देखते हुए , जो मुश्किल से चार साल की है , पिता के साथ नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा निश्चित रूप से गैरकानूनी है।नाबालिग जन्म से लेकर 16.11.2019 तक अपने माता/पिता के साथ रही है, जब पिता विशेष रूप से उसे यह कहते हुए अपने पैतृक घर ले गए कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अपने पति के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं

की क्योंकि उसे यह निष्कपट धारणा थी कि वह जल्द ही बेटी के साथ वापस आ जाएगा।इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्ता वैवाहिक मोर्चे पर भी व्यथित था , लेकिन सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए उसने किसी भी दीवानी और /या आपराधिक कार्यवाही को स्थापित आदेश के लिए जल्दबाजी करके मुद्दों को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि पति का कदाचार और षड्यंत्रकारी मानसिकता घटनाओं पर एक स्पष्ट नज़र से दिखाई देती है , और जिस तरह से, उन्होंने याचिकाकर्ता को बार -बार गुमराह करने के बाद हिरासत याचिका दायर की कि वह जल्द ही बेटी के साथ वैवाहिक घर लौटेंगे।

10. मामले में आगे बढ़ने से पहले , यह न्यायालय यह अवलोकन करना चाहेगा कि भले ही याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 के बीच उनके अंतर -वैवाहिक आचरण के संबंध में आरोप और जवाबी आरोप हैं , लेकिन इस स्तर पर उन्हें बिना किसी सौदे के छोड़ दिया जाना सबसे अच्छा है।इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नाबालिग बेटी के हित और कल्याण में सबसे अच्छा क्या है ताकि पिता या मां के साथ उसकी विशेष अंतरिम अभिरक्षा जारी रखी जा सके ?यह उपयुक्त न्यायालय पर है कि वह उन पति-पत्नी के आरोपों से उचित कार्यवाही में निपटे।

11. अब बच्ची **के हित और कल्याण और उसके परिणामी परिणाम की ओर ध्यान दिलाते हुए, कि उनके अलग होने के दौरान पति या पत्नी में से किसके पास नाबालिग बेटी की अभिरक्षा होनी चाहिए, यह न्यायालय यह कहना चाहेगा कि केवल इसलिए कि पक्षकारों के लिए अन्य उपाय उपलब्ध हैं, वर्तमान याचिका को विचारणीय नहीं बनाएगा।कानून में यह तय स्थिति है कि नाबालिग** बच्ची **की सुरक्षा, कल्याण और खुशी सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट बनाए रखा जा सकता है।ऐसे मामलों में, जो निर्णय लिया जाना है, वह केवल शामिल पति/पत्नी के कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि मुख्य रूप से, न्यायालय द्वारा अपनाया जाने वाला मानदंड यह है कि माता-पिता के हित के बजाय नाबालिग** बच्ची **के हित और कल्याण में क्या अधिक है।आखिरकार, हर बच्चा एक राष्ट्रीय संपत्ति है।यह अदालत का बाध्य कर्तव्य भी**

है कि वह संकट में पड़े बच्ची **के कल्याण और हित को देखे और सुनिश्चित करे, जो उसके पालन-पोषण के लिए सबसे उपयुक्त है।कहने का मतलब यह नहीं है कि माता-पिता का प्यार और स्नेह, उनके अधिकार और कर्तव्य और अन्य**

(जसजीत सिंह बेदी, जे.)

उनके बच्ची **को किसी भी तरह से कमजोर नही किया जाना चाहिए। सभी पर विचार करने के बाद** किसी भी तरीके से फायदे और नुकसान पर जोर देना चाहिए। अदालत केवल पूरक के लिए हैं।

13. एक अन्य पहलू जो यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वह है नाबालिग बेटी की कम उम्र।वह केवल चार साल की है और आम तौर पर, 1890 के अधिनियम की खंड 6 के अनुसार, पांच साल से कम उम्र की नाबालिग की अभिरक्षा उसकी माँ के साथ होनी चाहिए।तैयार संदर्भ के लिए, उक्त खंड को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"6. हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक-नाबालिग के व्यक्ति के साथ-साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक हैं -

(क) एक लड़के या एक अविवाहित लड़की के मामले में-पिता, और उसके बाद, माँ; बशर्ते कि एक नाबालिग की अभिरक्षा जिसने पाँच वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, आम तौर पर माँ के साथ होगी।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रावधान यह मानता है कि अभिरक्षा "आम तौर पर" मां के पास होगी।लेकिन "सामान्य रूप से" शब्द का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि जब तक, प्रथमदृष्टया, यह पिता द्वारा अन्यथा नहीं दिखाया जाता है कि मातृत्व से वंचित होने से बच्ची **की बेहतर देखभाल की जा सकती है।पिता को तब कुछ ठोस कारण देने चाहिए, जो** बच्ची बच्ची **के कल्याण और हित को खतरे में डालने या अनन्य मातृत्व के** बच्ची **के पालन-पोषण के लिए आसन्न रूप से गैर-अनुकूल होने का संकेत देते हैं।पारिवारिक परिदृश्य और परिस्थितियों में, ऐसा कोई ठोस तर्क सामने**

नहीं आ रहा है जिससे माँ के वैधानिक अधिकार को अस्वीकार किया जा सके।कहा गया मातृत्व अधिकार, वास्तव में, अनिवार्य रूप से नाबालिग बच्ची **के लाभ और कल्याण के लिए अधिक है।खंड 6 की भावना यह परिकल्पना करती है कि, नाबालिग की कम उम्र को देखते हुए, अभिरक्षा की उपयुक्तता प्रमुख कारक नहीं है, जो अधिक प्रासंगिक है या जिसे दबाव देना चाहिए, वह आवश्यक जैविक और प्राकृतिक वातावरण है, जो एक सामान्य धारणा को जन्म देता है कि माँ उस उम्र के नाबालिग की देखभाल के लिए सबसे पहले और सबसे उपयुक्त है।**

14. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जबकि कोई 436 नहीं है

इस प्रस्ताव के साथ असहमति कि प्रतिवादी संख्या 4 को यहाँ नाबालिग बेटी का पिता होने के नाते, उसकी अवैध या गैरकानूनी हिरासत में नहीं कहा जा सकता है, हालाँकि, चूंकि नाबालिग बेटी पांच साल से कम है, इसलिए माँ खंड 6, आई. बी. आई. डी. के लाभ की हकदार है।इसके अलावा, प्रथमदृष्टया, इस न्यायालय की राय है कि जब तक नाबालिग बच्ची **की अभिरक्षा के लिए पक्षकारों की प्रार्थना का निर्णय संरक्षक अदालत द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक नाबालिग** बच्ची **का कल्याण और हित मां-याचिकाकर्ता के हाथों में बेहतर होगा।**

15. इसमें शामिल बच्ची के कल्याण और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के संबंध में पूरे परिवार को ध्यान से सोचने के बाद , मेरी राय है कि प्रतिवादी संख्या 4 के साथ नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा जारी रखना वांछनीय नहीं हो सकता है।विशेष रूप से , जब नाबालिग बेटी अपने बचपन से ही माता -पिता दोनों के साथ थी , तब तक उसे पिता-प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा गुप्त तरीके से उसकी विशेष अभिरक्षा के लिए ले जाया गया था।

17. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 बच्ची के सर्वोपरि हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी /अंतरिम अभिरक्षा के लिए एक उचित नया आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।मेरी उपरोक्त टिप्पणियां केवल प्रारंभिक हैं

और संरक्षक न्यायाधीश, उनसे प्रभावित हुए बिना, खंड 25 के तहत लंबित याचिका पर विचार करेगा और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।चूंकि, प्रतिवादी नं . 4 को पहले ही स्वतंत्रता दी जा चुकी है। 4 इसलिए अभिरक्षा की मांग करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए , इस स्तर पर याचिकाकर्ता को नाबालिग की अस्थायी अभिरक्षा प्रदान करना उचित होगा जब तक कि संरक्षक/सिविल न्यायाधीश द्वारा कोई और उचित आदेश पारित नहीं किया जाता है।

मंदीप कौर बनाम पंजाब राज्य सी. आर. डब्ल्यू. पी. के मामले में -

8319-2020 10.05.2021 पर निर्णय लिया गया जहां पत्नी ने पति -पिता के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और ऑस्ट्रेलियाई अदालतों का एक अंतरिम आदेश था जिसमें पति को नाबालिग बच्ची को उसकी मां को वापस करने का निर्देश दिया गया था , इस अदालत ने माँ को हिरासत प्रदान करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"याचिकाकर्ता, जो माँ है, चार साल की बच्ची की अभिरक्षा की मांग कर रही है। बच्ची को उसके विकास के लिए माँ के प्यार, देखभाल और स्नेह की आवश्यकता होगी।

प्रारंभिक वर्ष।किशोरावस्था के दौरान माँ का समर्थन और मार्गदर्शन भी अनिवार्य होगा।हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम , 1956 की खंड 6 के अनुसार, माँ पाँच साल की उम्र तक बच्ची की स्वाभाविक अभिभावक होती है , जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"एक हिंदू नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक। — नाबालिग के व्यक्ति के साथ -साथ नाबालिग की संपत्ति के संबंध में (संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक संरक्षक हैं -(ए) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में -पिता और उसके बाद माँ◌ःबशर्ते कि पाँच वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होगी;

(ख) अवैध लड़के या अवैध अविवाहित लड़की के मामले में -माँ, और उसके बाद , पिता;

(ग) विवाहित लड़की के मामले में -पतिःबशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस खंड के प्रावधानों के तहत नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा -

((क) यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या

(ख) यदि उसने एक संन्यासी (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी) बनकर पूरी तरह से और अंत में दुनिया का त्याग कर दिया है।स्पष्टीकरण। — इस खंड में , "पिता" और "माँ" अभिव्यक्ति में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं हैं।"

मैं मंदीप कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले से भी समर्थन प्राप्त करता हूं , जिसमें साढ़े तीन साल की बेटी की अभिरक्षा मां को दी गई थी ; नेहा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (ऊपर) जिसमें चार साल की बच्ची की अभिरक्षा भी मां को सौंप दी गई थी।रजत अग्रवाल बनाम सोनल अग्रवाल , 2017 के एफ . ए. ओ. नं.4545 के मामले में इस अदालत की एक खण्ड पीठ 25.02.2021 पर निर्णय लिया था , जिसमें 13 वर्षीय बच्ची की मां को अभिरक्षा देने वाले परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था।फैसले के प्रासंगिक उद्धरण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"17. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए , हमारी विचारशील राय है कि प्रतिवादी -माँ नाबालिग को शिक्षित करने और लालन–पालन करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है।

उसकी नाबालिग बेटी और उसके हित और कल्याण का प्रभावी ढंग से ध्यान रखना।एक बच्ची के व्यक्तित्व के विकास में माँ की भूमिका पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है।माँ अपने बच्ची को हिलाकर , पोषित करके और निर्देश देकर पालने से बच्ची की दुनिया को आकार देती है।विशेष रूप से , एक माँ की संगति एक बढ़ती हुई

महिला बच्ची के लिए अधिक मूल्यवान है जब तक कि कोई सम्मोहक और उचित कारण न हों, एक बच्ची को माँ की संगति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

18. इसके अलावा, माँ एक अनमोल उपहार है , एक वास्तविक खजाना है और एक बच्ची के लिए एक गंभीर हार्दिक शक्ति है , विशेष रूप से 13 साल की उम्र की बढ़ती हुई लड़की के लिए जो उसके जीवन का महत्वपूर्ण चरण है जो जैविक रूप से सोचने में प्रमुख बदलाव है जो उसे अपनी माँ की मदद से अधिक प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है और इस महत्वपूर्ण किशोरावस्था में , माँ के साथ उसकी अभिरक्षा उसके विकास के लिए आवश्यक है।इस बढ़ती उम्र में , बेटी माँ /महिला साथी की तलाश करती है जिसके साथ वह कुछ मुद्दों को आसानी से साझा कर सकती है और चर्चा कर सकती है।ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिन पर एक बेटी अपने पिता के साथ चर्चा नहीं कर सकती थी और इस तरह इस बढ़ती उम्र में अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए मां सबसे अच्छी व्यक्ति होगी। " इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पास स्थायी निवास है

ऑस्ट्रेलिया।वह प्रति वर्ष 70,000/- ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कमा रही है और ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों द्वारा बच्ची **के रखरखाव के लिए उसे एक अच्छी राशि का भुगतान किया जाएगा।उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक घर खरीदा है।यद्यपि याचिकाकर्ता को अपनी शैक्षिक योग्यता का खुलासा करने में अधिक स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए था, फिर भी चूक इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे** बच्ची **की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए क्योंकि इस न्यायालय के लिए जो सर्वोपरि विचार है वह** बच्ची **का हित और कल्याण है।याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया में आगे की पढ़ाई के अवसरों का लाभ उठा सकती है और अपनी योग्यता बढ़ा सकती है।फिर भी वह ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत है और एक वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण कर रही है जो उसे अपनी अच्छी शिक्षा प्रदान करके** बच्ची **का पालन-पोषण करने में सक्षम बनाएगी।पिता ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं।उन्होंने आतिथ्य प्रबंधन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत हैं और हाल ही में भारत आया हैं।**

उसके पास कृषि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है और कहा जाता है कि उनकी कुछ किराये की आय भी है।

यह ध्यान देने योग्य है कि पार्टियां अपने करियर की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थीं।वे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। बच्ची का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और शुरुआती वर्षों में उनका पालन-पोषण वहीं हुआ था।आदर्श रूप से यह बच्ची के सर्वोत्तम हित और कल्याण में होगा यदि वह विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में माता-पिता दोनों का प्यार , स्नेह और संगति रखे।इस अदालत ने सुलह का विचार रखा था , लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई क्योंकि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहता है, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 भारत में बसना चाहता है , हालांकि उसके पास ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर डिग्री है और वहां उसकी संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई देती हैं।हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एकल माता -पिता द्वारा पाला गया बच्चा नुकसान में होगा।आधुनिक समय एकल माता -पिता द्वारा उठाए गए बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने वाले जिम्मेदार वयस्कों के रूप में बड़े होने के उदाहरणों से भरा हुआ है।

जसविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य में। जहाँ

माता ने दादा -दादी के खिलाफ एक मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जहां पिता का निधन हो गया था, इस अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“15. वर्तमान रिट याचिका में पहला विवाद यह है कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा सौंपने के लिए बनाए रखने योग्य है।इस सवाल का जवाब सकारात्मक है।जहां बच्चों की अभिरक्षा दूसरे पक्ष द्वारा बलपूर्वक ली गई है या उस मामले में कानूनी तरीके से नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है और अभिरक्षा का सहारा नाबालिगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अभिभावक को दिया जाना चाहिए।

20. दानदाताओं के छोटे कल्याण की अभिरक्षा प्रदान करते समय सर्वोपरि विचार किया जाता है।हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के अनुसार हिरासत को उन रिश्तेदारों को भी सौंपा जा सकता है जो प्राकृतिक अभिभावक नहीं हैं।

22. याचिकाकर्ता के मृत पति अनिल कुमार और नाबालिग बच्ची एकता और मोहित जालंधर में रह रहे थे।उस प्रभाव के लिए राशन कार्ड की प्रति है

फाइल पर रखा गया।यह भी विवादित नहीं है कि अनिल कुमार की बीमारी के बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई और उसके बाद नाबालिग की हिरासत को लेकर विवाद पैदा हो गया है।हिंदू कानून के तहत , हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम , 1956 लागू होने से पहले , पिता व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक थे और अपने नाबालिग बच्चों की अलग संपत्ति थे और उनके बगल में मां थी।

23. संरक्षक अधिनियम की खंड 6 में कहा गया है कि नाबालिग के व्यक्ति के साथ - साथ नाबालिग की संपत्ति (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) के संबंध में हिंदू नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक हैं:-

(क) एक लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में पिता , और उसके बाद माँ ; बशर्ते कि एक नाबालिग की अभिरक्षा जिसने पाँच साल की उम्र पूरी नहीं की है , आम तौर पर माँ के साथ होगी।माँ ; बशर्ते कि पाँच साल की उम्र पूरी करने वाले नाबालिग बेटे की अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होगी।

24. वर्तमान मामले में नाबालिगों की आयु 7 वर्ष और 9 वर्ष है अर्थात याचिकाकर्ता की बेटी एकता की जन्म तिथि 20.8.2000 है जबकि याचिकाकर्ता के बेटे मोहित की जन्म तिथि 25.8.2002 है।यह दोनों पक्षों का मामला है कि अनिल कुमार की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता गाँव चमियारी आया था और उसके बाद बच्ची गाँव चमियारी में रहे।याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे पीटा गया और उसे बच्चों को लेने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि प्रतिवादी का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से बच्चों को गाँव चमियारी में छोड़ दिया।हालाँकि , यह तथ्य विवादित नहीं है कि अनिल कुमार की मृत्यु से पहले बच्ची याचिकाकर्ता और मृतक अनिल कुमार के साथ

जालंधर में रह रहे थे।मृतक अनिल कुमार जालंधर में पुलिस विभाग में नौकरी करता था।प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के तीन बेटे और पोते -पोतियां हैं।वर्तमान याचिका , रिकॉर्ड के अनुसार , 14.7.2009 पर प्रस्तुत की गई है जबकि अनिल कुमार की मृत्यु 2.3.2009 पर हुई है।चमन लाल -प्रतिवादी ने संरक्षक अधिनियम की खंड 6 के साथ पठित अधिनियम की खंड 7 और 25 के तहत याचिका दायर की है, ताकि एकता और मोहित को उनके व्यक्ति और संपत्ति के संबंध में संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिरक्षा के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण उस याचिका में किया जाएगा, लेकिन पूरी परिस्थितियों पर विचार करते हुए

इस तथ्य को देखें कि नाबालिग 2.3.2009 तक याचिकाकर्ता और अनिल कुमार की हिरासत में थे।मेरा विचार है कि नाबालिगों के कल्याण के लिए , अधिनियम की खंड 25 के तहत आवेदन के निर्णय तक हिरासत माँ को सौंप दी जानी चाहिए।

25. वास्तव में प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने नाबालिग एकता और मोहित की अभिरक्षा से एक माँ को वंचित कर दिया था।इसलिए नाबालिगों की अभिरक्षा को वैध अभिभावक को बहाल करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट बनाए रखने योग्य है।जो दोनों नाबालिग की माँ थी।हालाँकि यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 नाबालिगों की अभिरक्षा के संबंध में चुनाव लड़ रहे हैं।इसलिए मेरे विचार में दादा - दादी को नाबालिगों से मिलने से वंचित नहीं किया जा सकता है।इसलिए अधिनियम की खंड 25 और 7 के तहत आवेदन के निर्णय तक , यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 को याचिकाकर्ता के निवास स्थान जालंधर में या हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को दोनों पक्षों के लिए सहमत स्थान पर नाबालिगों से मिलने का अधिकार होगा।

गुरमीत कौर बाठ बनाम अन्य पंजाब राज्य और अन्य में। सी. आर. डब्ल्यू. पी -

1165-2008 20.01.2009 पर निर्णय लिया गया जहां माँ ने दादी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और कनाडा के न्यायालय ने बच्ची की अंतरिम

अभिरक्षा माँ को दे दी थी , इस अदालत ने माँ को अभिरक्षा देते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

“19. यह रिट याचिका विचारणीय थी या नहीं , यह एक अन्य मामले 'गिप्पी अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य और अन्य ' आपराधिक रिट याचिका 2008 में एक विषय था , जिसका निर्णय इस न्यायालय ने 25 नवंबर, 2008 को किया था।पूरा मामला कानून माननीय न्यायाधीश श्री एम . एम. एस. बेदी द्वारा निपटाया गया था।विद्वतापूर्ण निर्णय में, मामले के कानून के पूरे पहलू में जाने के बाद , निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

“बच्ची की अभिरक्षा के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले , नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा के मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की रखरखाव के बारे में भौतिक प्रश्न का निर्धारण किया जाना चाहिए।यह कानून का एक तय सिद्धांत है कि नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा से संबंधित सभी विवादों में , नाबालिग का हित और कल्याण प्रमुख मानदंड है।माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती.

एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ और अन्य,

ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 3 एक आपराधिक रिट याचिका में नाबालिग बच्ची बच्ची **की अभिरक्षा से संबंधित विवाद पर विचार कर रहा था जिसमें एक**

नाबालिग बच्ची का जन्म भारतीय पिता से हुआ था और अमेरिकी माँ अमेरिकी नागरिक थीं।माता-पिता के तलाक पर उनकी देखरेख और संरक्षकता संयुक्त राज्य अमेरिका के सक्षम न्यायालय द्वारा मां को सौंपी गई थी। पिता को मिलने का अधिकार दिया गया था।उसने नाबालिग का भारत में अवैध रूप से अपहरण कर लिया।नाबालिग की अभिरक्षा के लिए माँ द्वारा दायर एक रिट याचिका पर , यह माना गया था कि माँ बच्ची के लिए सच्चे प्यार और स्नेह से भरी हुई थी और उस पर उसकी देखभाल करने, उसे शिक्षित करने और उसके उचित पालन-पोषण के लिए हर संभव तरीके से ध्यान रखने के लिए सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता था।भारत में बच्ची की उपस्थिति को अपहरण के एक अवैध कार्य का परिणाम माना

गया था और पिता को उक्त कार्य का दोषी ठहराया गया था जो किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था। 1996 (1) ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 886 पर भरोसा करते हुए, यह देखा गया कि सभी देशों में न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह देखें कि माता-पिता द्वारा बच्चों को अपने देश से बाहर निकालकर गलत काम करने से उन्हें अपने गलत काम से कोई लाभ न हो।मर्लिन ऐनत ढिल्लन के एक मामले में इसी तरह का सवाल इस अदालत के सामने आया है।

गिलमोर @अनीता ढिल्लों बनाम मार्गरिट निज्जर और अन्य,

1984 (1) आई. एल. आर. (पंजाब) 1, जहां माता-पिता संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे, लेकिन भारत आए थे , पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपने नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा के लिए याचिका दायर की थी।यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में बच्चों की अभिरक्षा के प्रश्न पर विचार कर सकता है।उक्त निर्णय के पैरा 17 में यह निम्नानुसार देखा गया थाः-

“17. बच्चों को माता-पिता दोनों के प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है।यदि वे इसे दोनों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें इसे एक से प्राप्त करना चाहिए।जो मार्ग उन्हें दोनों से वंचित कर देगा , उससे बचना चाहिए और अंतिम उपाय के रूप में अपनाया जाना चाहिए।बच्चों को तब तक किसी की अभिरक्षा में रहना आवश्यक है जब तक कि वे अपनी व्यस्क अवस्था प्राप्त नहीं कर लेते।इस मामले में रिट अधिकार क्षेत्र में आदेश पारित करने में न्यायालय को इसे न्यायसंगत तरीके से निपटना होगा।इसे मानव प्रकृति पर आधारित संबंधित माता -पिता के दावे को भी उचित महत्व देना होगा और आम तौर पर न्यायसंगत और न्यायपूर्ण क्या है।और प्रतिद्वंद्वी माता -पिता के अधिकारों और गलतियों के बावजूद , बंदी प्रत्यक्षीकरण के उपाय का उपयोग करते समय बच्चों का कल्याण सर्वोच्च विचार है।कानूनी टिप्पणीकारों द्वारा यह उचित रूप से देखा गया है कि इस तरह की कार्यवाही मुकदमाता में एक मुकदमे की घटना में भाग लेती है और एक विचार किया जाता है।

रेम में, बच्चा रेस है।"

बच्ची बच्ची बच्ची की अभिरक्षा माँ को सौंप दी गई थी , बशर्ते वह उच्च न्यायालय के समक्ष बांड निष्पादित करने के लिए वचन दे कि जब भी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए तो उन्हें पेश किया जाएगा।

सैयद सलीमुद्दीन बनाम डॉ. रुखसाना में,

ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2172, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के दायरे पर विचार करते हुए कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बनाए रखने योग्य है।जब तक परिवार न्यायालय बच्चों की अभिरक्षा के लिए याचिका का निपटारा नहीं करता , तब तक बच्चों की अभिरक्षा उनकी मां को देते हुए।इसे इस प्रकार देखा गयाः-

"उपरोक्त मामलों में निर्धारित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट की मांग करने वाले आवेदन में अदालत के लिए मुख्य विचार यह पता लगाना है कि क्या बच्चों की अभिरक्षा को गैरकानूनी या अवैध कहा जा सकता है और क्या बच्चों के कल्याण के लिए वर्तमान अभिरक्षा को बदलने की आवश्यकता है और बच्चों को किसी और की देखभाल और अभिरक्षा में छोड़ दिया जाना चाहिए।यह सिद्धांत अच्छी तरह से तय किया गया है कि बच्ची की अभिरक्षा के मामले में बच्ची का कल्याण न्यायालय के सर्वोपरि विचार का विषय है।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के फैसले से यह नहीं पता चलता है कि न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्नों पर कोई ध्यान दिया है।उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या तथ्यों और परिस्थितियों में बच्चों की उनके पिता के साथ अभिरक्षा को गैरकानूनी कहा जा सकता है।अदालत ने इस सवाल पर भी ध्यान नहीं दिया कि क्या बच्चों के कल्याण के लिए उन्हें उनके पिता की हिरासत से बाहर निकालकर उनकी मां की देखभाल में छोड़ दिया जाना चाहिए।हालाँकि , हमारे लिए श्री एम. एन. राव द्वारा दी गई उचित रियायत को देखते हुए इस प्रश्न पर आगे विचार करना आवश्यक नहीं है कि अपीलकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है यदि बच्ची

माता की अभिरक्षा में रहते हैं और पिता को उनसे मिलने का अधिकार है जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले में उल्लेख किया गया है , जब तक कि परिवार न्यायालय अपीलकर्ता द्वारा अपने बच्चों की अभिरक्षा के लिए दायर याचिका का निपटारा नहीं करता है।"

इसी तरह श्रीमती कुलदिप सिद्धू बनाम चानन सिंह और अन्य के मामले में, ए. आई. आर. 1989 पी. एंड एच. 103 के मामले में जहाँ माँ

विदेशी अदालत से उसके पक्ष में अंतरिम हिरासत का आदेश था और पिता ने अनधिकृत तरीके से बच्चों को कनाडा से भारत ले जाया गया , बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की अनुमति दी गई और बच्चों की अभिरक्षा को मां को सौंपने का निर्देश दिया गया।यूजेनिया में

अर्चेट्टी अब्दुल्ला बनाम केरल राज्य, 2005 (1) आर. सी. आर.

(सी. आर. एल.) 259, केरल उच्च न्यायालय के एक प्रभाग ने कहा कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों की गोद के लिए मां एक प्राकृतिक पालना है जहां बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है।उक्त मामले में 3 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों की हिरासत पिता के पास थी।पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके हिरासत का दावा किया था।यह निर्णय के बाद आयोजित किया गया था

मंजू तिवारी बनाम राजेंद्र तिवारी मामले में उच्चतम न्यायालय,

ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1156, कि उच्च न्यायालय अवैध निरोध या गलत हिरासत होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।इसी तरह गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने

सुरभाई रविकुमार मीनावाला बनाम गुजरात राज्य,

2005 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 822 में 9 महीने के बच्ची की अभिरक्षा के संबंध में माँ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी अनुमति दी गई थी जिसमें कहा गया था कि माँ की देखभाल और प्यार की जगह कोई भी धन राशि नहीं ले सकती है।ऐसा ही सवाल उठा था।

मंजीत कौर बनाम में इस न्यायालय के समक्ष। पंजाब राज्य, और क्र. सं. 2008 का डब्ल्यू. पी. सं. 608,14 अगस्त, 2008 को तय किया गया

जहां 9 महीने के एक नाबालिग बच्ची को उसके दादा -दादी द्वारा ले जाया गया था जब उनकी बहू, एक एनआरआई, थोड़े समय के लिए विदेश से आई थी।इस अदालत ने मंजू तिवारी के मामले (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय है क्योंकि बच्ची को अवैध रूप से मां से छीन लिया गया है। बच्ची की अभिरक्षा मां को सौंप दी गई और पक्षों को कानून के अनुसार अन्य उपायों का लाभ उठाने के लिए छोड़ दिया गया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील श्री जौहर ने जोरदार तर्क दिया है कि बच्ची की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है।याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय परिवार न्यायालय से संपर्क करना है जहां वैवाहिक विवाद लंबित है और इसे नाबालिग बच्ची के कल्याण का निर्धारण करने के लिए उक्त न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए।वह इस पर मजबूत निर्भरता रखता है

शीला बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य, 149 (2008) दिल्ली लॉ टाइम्स 476 (डी. बी.) का निर्णय।

मैंने उक्त निर्णय को ध्यान द्वारा देखा है।उक्त मामले में एक रिट याचिका में पत्नी द्वारा दिए गए वचन के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पत्नी को बच्ची की अभिरक्षा दी गई थी, लेकिन अंतरिम निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उसे फिर से पिता को सौंप दिया गया था।पत्नी का आचरण अनुचित था।रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और पक्षों को उचित मंच पर बच्ची की अभिरक्षा के लिए लड़ने के लिए छोड़

दिया गया।रिट याचिका की गैर -रखरखाव के संबंध में कोई आत्यन्तिक नियम या कानून निर्धारित नहीं किया गया था।प्रतिवादी के वकील सैहबा अली बनाम राज्य **महाराष्ट्र और अन्य, 2003 (4) आरसीआर (सिविल)** 273:(2003) 7 एससीसी 250 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते है। उक्त मामले में , सक्षम परिवार न्यायालय के आदेश के तहत नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा दादा -दादी के पास थी।पत्नी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की थी जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी जिसमें प्रतिवादी को नाबालिग बच्ची को पेश करने और उसे उसकी अभिरक्षा सौंपने का निर्देश दिया गया था।उच्चतम न्यायाधीशालय ने अभिनिर्धारित किया कि रिट बनाए रखने योग्य नहीं थी , लेकिन निर्णय के पैरा 5 में कहा गया कि पूर्ण न्यायाधी देने के लिए, न्यायाधीशालय नाबालिग बच्चों के हित और कल्याण में एक आदेश पारित कर सकता है कि माँ को मिलने का अधिकार दिया जाए , लेकिन यह कभी निर्धारित नहीं किया गया था कि रिट याचिका में भी पूर्ण न्यायाधी देने के लिए रिट याचिका में कोई राहत नहीं दी जा सकती है।उन्होंने एक फैसले पर भी भरोसा किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से मंजुला झा बनाम रवींद्र नाथ झा, 1998 (1) अखिल भारतीय हिंदू विधि रिपोर्टर 273.में।

उक्त मामले में, माँ ने एक रिट याचिका में बच्ची को पेश करने और बच्ची को उसे देने की मांग की थी।याचिका को खारिज कर दिया गया था , हालांकि, बच्ची को एक निश्चित तिथि पर संरक्षक न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष पेश करने और अंतरिम हिरासत की रिट निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था।प्रतिवादी के वकील ने वैदेही बनाम पर भी भरोसा जताया। आई.

गोपीनाथ, 1993 (2) अखिल भारतीय हिंदू विधि रिपोर्टर, 647 में

जहाँ एक माँ ने अपने पति के खिलाफ 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु के दो नाबालिग बच्चों को पैदा करने और उन्हें माँ को सौंपकर उन्हें मुक्त करने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी।बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी गई थी लेकिन

याचिका को खारिज करते समय मुख्य विचार यह था कि अदालत में पेश किए गए दोनों बच्चों ने बयान दिए थे जो दर्ज किए गए थे।उक्त बयानों में उनके पास थे।

माँ के साथ नहीं रहने की इच्छा व्यक्त की और अपने पिता के साथ रहना पसंद किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा रखा गया है।

बग्गा (श्रीमती) बनाम पंजाब राज्य और दूसरा, 1996 (2) आर. आर. आर. 202:1996 (1) अखिल भारतीय हिंदू विधि रिपोर्टर 683।में।

उक्त मामले में, बच्ची की अभिरक्षा से संबंधित कार्यवाही संरक्षक न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी , लेकिन मां ने बच्ची की अभिरक्षा के लिए उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।याचिका खारिज कर दी गई थी , हालांकि, संरक्षक न्यायाधीश को तीन महीने की अवधि के भीतर मामले का फैसला करने का निर्देश दिया गया था।उक्त मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं किया गया।प्रतिवादी के वकील द्वारा एक और निर्णय पर भरोसा किया गया

सुमनलता बनाम ओम्परक्ष सैनी और अन्य, 1990 (1) अखिल भारतीय हिंदू विधि रिपोर्टर, 286, जहां यह आयोजित नहीं किया गया था।

यह कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय नहीं है , लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के इतिहास और दायरे का पता लगाने के बाद , यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां नाबालिग का सर्वोपरि हित किसी कार्रवाई की मांग नहीं करता है, वहां न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने में धीमा होगा।नाबालिग की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के दायरे और उद्देश्य पर चर्चा करने के बाद , माँ की रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

प्रतिवादी के वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों को ध्यान से देखने के बाद , मेरी राय है कि उक्त निर्णयों में से किसी में भी यह कानून के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया

गया है कि एक प्राकृतिक अभिभावक द्वारा बच्ची को पेश करने और उसकी अभिरक्षा के सभी मामलों में केवल इसलिए खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी अन्य न्यायालय यानी संरक्षक न्यायाधी की अदालत के लिए है कि वह किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नाबालिग बच्ची के कल्याण के प्रश्न का निर्धारण करे।मंजू तिवारी के मामले (ऊपर) और यूजेनिया आर्चेटी अब्दुल्ला के मामले (ऊपर) में केरल उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसलों के अनुपात को देखते हुए , इस न्यायालय की राय है कि उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है , जब बच्ची की अभिरक्षा को एक स्वाभाविक अभिभावक द्वारा दूसरे पर धोखाधड़ी करके छीन लिया गया हो।"

(1) श्री नवकिरण सिंह ने भी सुमेधा पर भरोसा किया है।

नागपाल बनाम दिल्ली राज्य और अन्य 2000 (9) सुप्रीम

अदालती मामले 745 में कहा गया है कि जब तक बच्ची की संरक्षकता का मुद्दा तय नहीं हो जाता, तब तक बच्ची की अभिरक्षा मां को नहीं दी जा सकती है।

(2) मेरा विचार है कि यह निर्णय प्रतिवादी दादी के वकील के लिए कोई मददगार नहीं है।वर्तमान मामले में , बच्ची की देखभाल माँ द्वारा दादी को सौंपी गई थी।इसलिए, बच्ची की वापसी के लिए मां द्वारा की गई मांग पर , वह बच्ची का पालन करने और उसे वापस करने के लिए बाध्य है क्योंकि वह एक प्राकृतिक अभिभावक नहीं है।प्रतिवादी दादी 2008 के सिविल संशोधन संख्या 757 में संरक्षक न्यायाधीश और इस न्यायालय के समक्ष विफल रही हैं।इसके अलावा , कनाडा में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय ने माना है कि माँ बच्ची की अभिरक्षा की हकदार है।अन्यथा भी, माँ की गोद प्राकृतिक पालना है।इसलिए, प्रतिवादी इस न्यायालय में बच्ची को पेश करने और माँ को सौंपने के लिए बाध्य है , जो एक स्वाभाविक अभिभावक है।याचिकाकर्ता माँ को यात्रा दस्तावेजों के साथ बच्ची को कनाडा ले जाने की अनुमति होगी।

(16) विभिन्न निर्णयों (ऊपर दिए गए) के साथ हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की खंड 6 के अवलोकन से पता चलेगा कि बाल अभिरक्षा मामलों में सामान्य उपाय हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 और संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत निहित है।दीवानी अदालतों द्वारा की जाने वाली जांच और एक रिट कोर्ट द्वारा शक्तियों के प्रयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं जो संक्षिप्त प्रकृति का है जहां हलफनामों के आधार पर अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।इसलिए, जहां अदालत का विचार है कि एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है , वहां अदालत एक रिट कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकती है और पक्षों को दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दे सकती है।इसलिए, यह केवल असाधारण मामलों में है , जहां नाबालिग की अभिरक्षा के लिए पक्षों के अधिकारों का निर्धारण बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका में असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया जाएगा।इस प्रकार , जहां किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में सिविल न्यायालयों का सामान्य उपचार या तो उपलब्ध नहीं है या अप्रभावी है, वहां बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट निश्चित रूप से बनाए रखने योग्य है , इसलिए, जहां यह दिखाया गया है कि माता -पिता या अन्य लोगों द्वारा नाबालिग बच्ची को हिरासत में रखना अवैध था, बिना किसी कानून के अधिकार के और बच्ची के नुकसान के लिए भी था।

(17) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वोपरि विचार

बच्ची का कल्याण होना चाहिए और बच्ची के आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास, परिचित परिवेश आदि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची के कल्याण और हित के सवाल को अपने बच्चों के लिए मां के प्यार और स्नेह की स्वीकृत श्रेष्ठता के विचार पर आंका जाना चाहिए।माँ की गोद एक प्राकृतिक पालना है जहाँ बच्ची की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है और इसका कोई विकल्प नहीं है।माँ के प्यार और देखभाल की जगह माँ जैसी कोई भी संपत्ति या माँ

नहीं ले सकती है और इसलिए, बच्ची के स्वस्थ विकास के लिए मातृ देखभाल और स्नेह अपरिहार्य है।

(18) वर्तमान मामले में, अवनीत तुर्का नाम की लड़की का जन्म 01.08.2017 को हुआ था और इसलिए उसकी उम्र पाँच साल से कम है।प्रतिवादी नं .7 & 8 द्वारा उसे 23.01.2020 को भारत वापस लाया गया। जिसके बाद COVID-19 के कारण याचिकाकर्ता-माँ मार्च 2022 तक उसे देखने में असमर्थ थी।इसलिए , यह स्पष्ट है कि जब बच्ची ने याचिकाकर्ता का साथ छोड़ दिया तो वह लगभग ढाई साल की थी और उसने अपने बढ़ते हुए साल अपने दादा -दादी यानी प्रतिवादी नं . 7 और 8.पिता के अनुसार, बच्ची ने उस समय याचिकाकर्ता के साथ जाने से इनकार कर दिया था जब याचिकाकर्ता 28.03.2022 पर अपने माता-पिता के घर के लिए रवाना हुई थी।मैं यहां यह इंगित कर सकता हूं कि भले ही पिता के बयान को सच्चाई के रूप में लिया जाए कि बच्ची ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया था , लेकिन अपने आप में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इतनी कम उम्र का बच्चा नहीं जानता कि उसके सर्वोत्तम हित में क्या है।यह दोहराया जा सकता है कि बच्चा जनवरी 2020 से मार्च 2022 के बीच दो वर्षों में अपनी माँ से नहीं मिला था।जाहिरा तौर पर , अपने नियंत्रण से परे कारणों से याचिकाकर्ता भारत वापस आने में असमर्थ थी। नाबालिग लड़की ने प्रतिवादी संख्या 7 और 8 के साथ एक बंधन विकसित किया होगा। प्रतिवादी नं. 7 और 8 जिनके साथ वह पिछले दो साल से अधिक समय से रह रही है , जिसके कारण उसने कहा होगा कि वह अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती है।हालांकि , लंबे समय में बच्ची के लाभ और कल्याण के लिए , किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि बच्ची के कल्याण का बेहतर ध्यान दादा -दादी यानी मां द्वारा रखा जाएगा।अन्यथा भी, 05 वर्ष से कम आयु के बच्ची के मामले में (जो यहाँ मामला है) अभिरक्षा आम तौर पर माँ के पास होनी चाहिए।वास्तव में प्रतिवादी संख्या 7 और 8 द्वारा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है। बच्चे की देखभाल माँ के पास क्यों नहीं होनी चाहिए।

(19) जहाँ तक बच्ची की अभिरक्षा साझा करने का सवाल है , माँ ऑस्ट्रेलिया की निवासी है और पिता भी।प्रतिवादी नं। 7 और 8 (बच्ची के दादा -दादी) भारत के निवासी हैं।

भारत, और इसलिए, पिता का बयान कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी सं। 7 & 8 हिरासत साझा करना अतार्किक और अनुचित है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बच्ची की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य आदि के मुद्दे उत्पन्न होंगे और इन्हें माँ द्वारा सबसे अच्छी तरह से निपटाया जाता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि माँ नाबालिग बच्ची को बनाए रखने में पूरी तरह से असमर्थ है।

(20) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए , वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है।प्रतिवादी नं . 3 और 4 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि नाबालिग बच्चे, अर्थात् अवनीत तुर्का की अभिरक्षा प्रतिवादी नं. 7 और 8 (दादा-दादी) तुरंत याचिकाकर्ता (मां) को। इसके अनुसरण में, इस आदेश के अनुपालन के संबंध में एक शपथ पत्र प्रतिवादी सं। 3 और 4 याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्ची की अभिरक्षा सौंपने के एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को।

(21) उपरोक्त शर्तों में निपटाया गया।

ऋतंभ्र ऋषि

अस्वीकरण :– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सज्जन सिंह, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।